04 - लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया पर एआई का शिकंजा

05 - 'अरे कहना क्या चाहते हो-अच्युत पोतदार'

A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025

06 - विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे की आमला नगर को सौगात , सवा दो करोड़...

07 - गंभीर परिस्थितियों में मरीज की जान बचाने के लिए करें एयर...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 22, अंक 341, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

बेटियों को जायदाद में हक देने के फैसले से आदिवासियों में हलचल क्यों?

आलोक पुतुल

सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फ़ैसले ने आदिवासी स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में हक़दार बना दिया है। यह महज एक क़ानूनी फ़ैसला नहीं है। यह सदियों पुरानी आदिवासी परंपराओं के समंदर में फेंका गया एक पत्थर है। इससे पैदा हुई लहरों की गूँज कई जगह महसूस की जा रही है।

यह कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के मानी गाँव से। पाँच आदिवासी भाइयों की एक बहन थी धइया। पिता की संपत्ति में धइया की हिस्सेदारी की बात आई, तो भाइयों ने साफ़ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आदिवासियों में बेटियों को संपत्ति में हिस्सा देने की परंपरा नहीं है। धइया के बेटे-बेटियों ने अपनी माँ के हक़ के लिए अदालत में गुहार लगाई। सूरजपुर से होते हुए यह मामला दिल्ली तक पहुँचा।

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि धइया को भी पिता की संपत्ति में हक़ मिलना ही चाहिए। हालाँकि, धइया अब जीवित नहीं हैं। दूसरी ओर, आदिवासी संगठन इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। धइया के बेटे रामचरण सिंह कहते हैं, 'मुझे नहीं पता कि नाना की संपत्ति में हक़ मिलेगा या नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि आदिवासी समाज मेरे हक़ की लड़ाई के खिलाफ़ है। मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी माँ के हक़ के लिए 1993 में क़ानूनी लड़ाई की शुरुआत की थी। मैंने 32 साल लड़ाई लड़ी। अंततः लड़ाई में जीत हासिल की।'

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक़, भारत में आदिवासियों की आबादी देश की कुल जनसंख्या का 8.6 फ़ीसदी हैं। देश के अधिकांश आदिवासी समुदायों में बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की एक मामूली-सी संपत्ति से जुड़ा अदालत का फ़ैसला, 730 अलग-अलग समुदायों वाली आदिवासी आबादी पर असर डालेगा।

इस कहानी को संक्षेप में समझें, तो सूरजपुर के मानपूर गाँव के भज्जू गौड़ उर्फ़ भजन शोरी के पाँच बेटे और एक बेटी धइया थी। धइया की शादी रगम साई से हुई। शादी के बाद वह ससुराल में ही रहने लगी। जब संपत्ति के बँटवारे की बात आई, तो भज्जू गौड़ ने अपनी ज़मीन बेटों में बाँट दी। धइया के बेटों ने दावा किया कि संपत्ति में उनकी माँ को भी बराबर का हक़ मिलना चाहिए।

धइया के बेटे रामचरण कहते हैं, 'हमें कहा गया कि आदिवासियों में बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक़ नहीं मिलता। हमने आवाज़ उठाई, तो आदिवासी रीति-रिवाजों का हवाला दे कर हमें चुप करा दिया गया। इसके बाद हमने सूरजपुर की अदालत में साल 1993 में मामला दायर किया।' मामला छोटी अदालत से अतंतः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यहाँ पिछले महीने न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करना अनुचित और भेदभावपूर्ण है।

हालाँकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि आदिवासी महिलाओं को स्वतः ही विरासत के अधिकार से बाहर कर दिया जाए। यह देखना आवश्यक है कि क्या कोई ऐसा प्रचलित रिवाज है, जो आदिवासी महिला सदस्यों को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचित करता है?

अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई भी पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका कि ऐसा कोई रीति-रिवाज अस्तित्व में है, जो महिलाओं को उत्तराधिकार से बाहर करता हो। अदालत का कहना था कि अगर ऐसा कोई रिवाज हो भी, तब भी उसे समय के साथ विकसित होना चाहिए। रिवाज भी, क़ानून की तरह स्थिर नहीं रह सकते और किसी को भी इनकी आड़ लेकर दूसरों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लिंग के आधार पर उत्तराधिकार से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

'छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला बताती हैं कि हिंदू महिलाओं को साल 2005 के हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति में हक़ मिला था। हालाँकि, इस अधिनियम से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है।'

'अब बड़ा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से सदियों पुरानी आदिवासी परंपरा टूटेगी? क्या आदिवासी बेटियों के लिए भी पैतृक ज़मीन-जायदाद में हिस्से का रास्ता खुलेगा? याचिकाकर्ता रामचरण के बेटे सदन टेकाम मानते हैं कि इस फ़ैसले से आदिवासी समाज में बड़ा बदलाव आएगा। बेटियों को भी जायदाद में हक़ मिलना चाहिए।'

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज का एक हिस्सा इस फ़ैसले से नाराज़ और चिंतित है। बस्तर में सर्व आदिवासी समाज के प्रकाश ठाकुर ने अपने लिखित बयान में कहा, 'इस फ़ैसले से आने वाले समय में पूरे देश में घर-घर में गृह युद्ध छिड़ने की प्रबल आशंका को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फ़ैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। गोंड आदिवासी समाज में महिलाओं को अपने पति की संपत्ति पर 100 फ़ीसदी अधिकार होता है। पिता की संपत्ति में बेटी को परंपरागत रूप से हिस्सा नहीं दिया जाता।'

वहीं पूर्व केन्द्रीय मंत्री व आदिवासी नेता अरविंद नेताम का कहना है कि आदिवासी ज़मीन किसी आदिवासी को ही बेची जा सकती है। उनका आरोप है कि पिछले कुछ सालों में ग़ैर-आदिवासी, आदिवासी लड़कियों से ब्याह कर रहे हैं। ज़्यादातर का मक़सद सिर्फ़ इतना भर रहता है कि आदिवासी ज़मीन ख़रीदी जा सके। इन सबके बीच, कई आदिवासी युवा और महिलाएँ सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से खुश हैं।

'अभिनव शोरी बस्तर के युवा आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि किसी संभावित नुक़सान के डर से किसी को उसके मूल अधिकार से वंचित करना संविधान सम्मत नहीं है। कांकेर की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता वंदना कश्यप का कहना है कि समय के साथ बदलाव आना ही चाहिए। खान-पान से लेकर पहनावा-ओढ़ावा तक सारे बदलाव हमने स्वीकार किए हैं। ऐसे में परंपरा के नाम पर संपत्ति के अधिकार से बेटियों को वंचित नहीं किया जा सकता है। इस बदलाव का भी हमें खुल कर स्वागत करना चाहिए।'

'वहीं, बरसों से छत्तीसगढ़ में महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता इंदू नेताम इसे क्रांतिकारी और ज़रूरी फ़ैसला मानती हैं। यह आदिवासी महिलाओं की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बड़ा फ़ैसला है।'

पैतृक विरासत की ज़मीन पर आदिवासी लड़कियों की राह बनाता सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फ़ैसला, धरातल पर किस हद तक उतर पाएगा, अभी कहना मुश्किल है। हाँ, इतना तय है कि इस फ़ैसले ने एक बड़ी बहस शुरू कर दी है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर पीएम-सीएम का पद जाएगा

● 5 साल+ सजा वाले अपराध में लागू होगा, सरकार बिल लाई ● विपक्ष का विरोध, जमकर हंगामा, जेपीसी को भेजा

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए। इसमें यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है, जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ये तीनों बिल हैं...गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया। सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की।

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल तो पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। केंद्र सरकार के मुताबिक,यह कानून यह रोकने के लिए जरूरी है।

मैंने गिरफ्तारी से पहले दे दिया था अपने पद से इस्तीफा

अमित शाह ने लोकसभा में के सी वेणुगोपाल को सुना दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तीन बिल पेश किए। इसमें कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 भी पेश किया। इस बिल का विपक्षी सांसद जोरदार विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान केरल के अलझुपा से कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे अपने ऊपर आरोप लगने के बाद भी नैतिकता का पालन नहीं किया था। उनके इस आरोप पर शाह बिफर गए और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो ना.. पहले बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड साफ करना चाहता हूं कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने अरेस्ट होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

शशि थरूर ने फिर पकड़ी कांग्रेस से अलग राह

नई दिल्ली (एजेंसी)। कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी पार्टी लाइन से हटकर बड़ा बयान दिया है। थरूर ने दागी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को जबरन हटाने संबंधी प्रस्तावित बिल का समर्थन किया है। थरूर ने कहा, अगर आप 30 दिन जेल में बिताएं, तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हैं। यह सामान्य ज्ञान की बात है... मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। थरूर ने कहा कि अगर इस बिल को अध्ययन के लिए समिति के पास भेजा जाता है, तो यह अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि समिति के भीतर चर्चा होना हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है... तो चलिए, इस पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को लेकर दोराहे पर खड़े शशि थरूर ने सोमवार को भी तब सभी लोगों को चौंका दिया था, जब उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर संसद में विशेष चर्चा में शामिल न होने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष किया।

अच्छा काम करेंगे तो सरकार आपके साथ : सीएम यादव

रैंकिंग के चक्कर में झूठा डेटा रिपोर्ट न करें : सीएस

भोपाल (नप्र)। मप्र में पिछले साल एक जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक नीति आयोग द्वारा चलाए गए संपूर्णता अभियान में अच्छा काम करने वाले जिलों के कलेक्टर और तत्कालीन कलेक्टरों को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए समारोह में नीति आयोग के सचिव रोहित कुमार, सदस्य रमेश चंद्र, प्रभारी मंत्री चेतन्य काश्यप, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी और अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

इस दौरान सीएम ने 'एमपी नीति आयोग' की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी का दर्शन है कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव और सुधार लाया जाए। देश और प्रदेश के सभी जिले, ब्लॉक और हर इकाई में हर योजना का लाभ सीधे आम जनता तक पहुँचना चाहिए। हम कई लोकलुभावन योजनाओं पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें बारीकी से देखने की जरूरत है। उन्होंने इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां वर्षा बहुत सीमित होती है, लेकिन तकनीक की मदद से पानी की व्यवस्था की जाती है। योजना आयोग का कार्य प्रणाली आज तक समझ में नहीं आया। बड़े सेक्टर में हम पीछे रह गए थे।

2014 के बाद पीएम मोदी ने पूरा परिदृश्य बदल दिया। कई सेक्टर में नवाचार किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। 2003 तक प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 30 कॉलेज बनने जा रहे हैं और अगले सवा साल में 10 और खुलेंगे। इसके साथ ही हर संभाग में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा।

सीएस अनुराग जैन ने कहा-मेरी सभी साथियों से गुजारिश होगी कि ये सुनिश्चित करें कि यह कल्चर नीचे तक पहुंचे। गलत सही जो भी है इस चक्कर में न पड़ें कि हमारी रैंकिंग बढ़ेगी या कम हो जाएगी। डेटा सही कैप्चर करें। यदि डेटा सही कैप्चर होगा तो हमें वास्तविकता का ज्ञान मिलेगा और उस हिसाब से हम डेटा बेस्ड पॉलिसी में सही निर्णय ले सकेंगे। यदि हमारे यहां नीचे लोगों ने रैंकिंग के चक्कर में झूठ बोलना शुरु कर दिया तो आंकड़े बड़ी अच्छी रोजी पिक्चर दिखाएंगे।

8 जिलों के अधिकारियों को गोल्ड मैडल

आज 8 जिलों के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें गोल्ड मैडल दिया गया, जबकि बाकी अवॉर्ड अन्य जिलों में भेजे जाएंगे। बड़वानी के कलेक्टर गुंचा सनोबर छुट्टी पर होने के कारण अवॉर्ड लेने नहीं आ सकी। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर राहुल हरिदास और दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर को गोल्ड मैडल दिया गया।

सुप्रभात

अपनी ही राख से बने आदमी
स्पंज की तरह होते हैं
जहाँ से भी दबाओ पिचक जाते हैं।
अपनी ही राख से बने आदमी
मोम की तरह होते हैं
जरा–सी आँच से पिघल जाते हैं।
वे क्रोध नहीं करते
प्रतिरोध नहीं करते
कोई शिकायत नहीं करते
सब सह लेते हैं चुपचाप।
वे अदेह से घूमते हैं
और किरायेदार की तरह रहते हैं
दुनिया में।
वे आग और पानी की बात नहीं करते
वे अस्पताल और श्मशान की तरफ
नहीं देखते।
मृत्यु उनके लिए भविष्य नहीं
अतीत की घटना है।

– चंद्रशेखर साकल्ले

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला

● सिर पर चोट, आरोपी गुजरात का, दावा-बंगले की रेकी की, सीसीटीवी में भी दिखा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान में कहा, आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर हमला किया। उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ की जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा– आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा। वे मेज के कोने से टकराईं। सिर पर चोट आई है। मीडिया में चल रही थप्पड़ वाली बात गलत है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पर अटेम्प्ट टू मर्डर (हत्या की कोशिश) का केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी को आज ही कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। आरोपी का नाम राजेशभाई खीमजीभाई सकरिया (41) है। वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है।

देश का सबसे चौड़ा सिक्स लेन पुल

यहां नीचे चलेंगे जहाज

बिहार में गंगा नदी पर बना, पीएम 22 अगस्त को करेंगे उद्घाटन

पटना (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गंगा नदी पर बने बिहार के पहले सिक्स लेन पुल औंटा (मोकामा)-सिमरिया (बेगूसराय) का उद्घाटन करेंगे। यह पुल उत्तर बिहार और पटना के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा। यह देश का सबसे चौड़ा सिक्स लेन पुल है। औंटा-सिमरिया पुल की चौड़ाई 34 मीटर है, जो सामान्य छह लेन पुल (29.5 मीटर) से 4.5 मीटर अधिक है। इसकी वजह से एक साथ ज्यादा वाहन आसानी से गुजर सकेंगे।

पथ निर्माण विभाग के मुताबिक, यह देश के सबसे चौड़े सिक्स लेन पुलों में शामिल है। यह एक एक्सपैंशन केबल ब्रिज है, जिसके नीचे से बड़े मालवाहक जहाज भी गुजर पाएंगे। एप्रोच रोड सहित पुल की कुल लंबाई 8.150 किमी है, जबकि गंगा पर मुख्य पुल की लंबाई 1.865 किमी है। इस प्रोजेक्ट पर 1871 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसकी परिकल्पना पथ निर्माण विभाग के पूर्व प्रधान सचिव और मौजूदा मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में बिहार पैकेज के तहत इस पुल की घोषणा की थी और 2017 में शिलान्यास किया था। यह पुल पुराने दो लेन के राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। नए पुल से भारी वाहनों की आवाजाही तेज और आसान होगी, ईंधन की बचत होगी और उत्तर बिहार के कई जिलों का पटना से सीधा संपर्क हो जाएगा। इसके साथ ही बख्तियारपुर-मोकामा चार लेन सड़क का उद्घाटन भी किया जाएगा। औंटा-सिमरिया पुल बिहार की पहली परियोजना है जो हैम (हाइब्रिड एन्यूटि मॉडल) में बनी है। इसमें निर्माण करने वाली कंपनी 60 फीसदी खर्च वहन करती है और सरकार केवल 40 फीसदी देती है। गंगा नदी पर कच्ची दरगाह-बिदुपुर और शेरपुर-दिघवारा के बीच भी छह लेन पुल बन रहे हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 21 अगस्त 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

● अमेरिका बोला-इससे यूक्रेन जंग रोकने में मिलेगी मदद

भारत पर प्रतिबंध का मकसद रूस पर दबाव बनाना

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लीविट ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले तक ट्रम्प प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पैनल्टी या टैरिफ बताता रहा है। ट्रम्प ने भारत पर अब तक कुल 50 टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसमें 25 फीसदी रेसीप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25 फीसदी पैनल्टी है। रेसीप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया है, जबकि पेनल्टी 27 अगस्त से लागू होगी। लीविट के मुताबिक इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है, ताकि वह युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो। उन्होंने कहा- लीविट ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक संघर्ष को रोकने में ट्रम्प ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक ट्रम्प ने व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर इस संघर्ष को खत्म कराया। लीविट ने कहा कि ट्रम्प ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पीस डील कराई। साथ ही रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच संघर्ष खत्म करने में मदद की। व्हाइट हाउस के मुताबिक, फिलहाल ट्रम्प का सबसे ज्यादा ध्यान रूस-यूक्रेन और इजराइल-हमास जंग को खत्म कराने पर है। ट्रम्प पहले भी कई बार भारत-पाक संघर्ष को खत्म कराने का श्रेय खुद को दे चुके हैं। ट्रम्प ने सोमवार देर रात (भारतीय समयानुसार) व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। ट्रम्प ने इस बातचीत को सफल बताया। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि यह अब तक की उनकी सबसे अच्छी बातचीत रही। हालांकि, इस दौरान रूस-यूक्रेन के बीच सीजफायर पर सहमति नहीं बनी। ट्रम्प ने कहा कि

फिलहाल इतनी जल्दी सीजफायर संभव नहीं है। मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। ट्रम्प ने मीटिंग रोककर पुतिन से फोन पर 40 मिनट बात की। इस दौरान पुतिन ने रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सीधे बातचीत का समर्थन किया। यह बातचीत अगले 15 दिन के भीतर होगी। मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से 90 अरब डॉलर (करीब 8 लाख करोड़ रुपए) के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। पुतिन और ट्रम्प ने पिछले हफ्ते 15 अगस्त को देर रात अलास्का में मुलाकात की थी। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मॉड्यूल जारी किया

● क्लास 3-12 के सप्लीमेंट्री मटेरियल में किया गया है शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर पर एनसीईआरटी (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) ने दो स्पेशल मॉड्यूल जारी किए हैं। इन्हें क्लास 3 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पर शामिल किया गया है। मॉड्यूल में बताया गया है कि पाकिस्तान भले ही पहलगाम आतंकी हमले में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन यह हमला पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप के सीधे आदेश पर हुआ था। ये मॉड्यूल स्कूली बच्चों के बीच भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जागरुकता बढ़ाने के मकसद से बनाए गए हैं। क्लास 3 से 8 के लिए मॉड्यूल का टाइटल ऑपरेशन सिंदूर-वीरता की गाथा और 9 से 12 तक के लिए मॉड्यूल का टाइटल ऑपरेशन सिंदूर- सम्मान और बहादुरी का मिशन है। एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल रेगुलर कोर्स का हिस्सा नहीं होते। इसे कोई खास टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पर तैयार किया जाता है। इसे वाद-विवाद के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है।

मऊ एमएलए अब्बास अंसारी की नहीं जाएगी विधायकी

● भड़काऊ भाषण मामले में हाईकोर्ट ने रद्द की 2 साल की सजा

मऊ (एजेंसी)। यूपी की मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। भड़काऊ भाषण के मामले पर उनकी विधायकी नहीं जाएगी। निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा को उच्च अदालत ने रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि अब मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सजा का फैसला रद्द कर दिया है। इस बारे में 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब उनकी विधायक की बहाल हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में हुई सजा स्थगित कर दी थी। आज इसका फैसला न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। उल्लेखनीय है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एमएलए रहे अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य सरकार के अधिकारियों को परिणामों की धमकी दी थी। इस मामले में ट्रायल के बाद मऊ की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 189 (सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत अपराध के लिए कैद की सजा सुनाई थी।

फेफड़ों पर हावी हो रहा रेस्पीरेट्री सिंसेशियल वायरस

बच्चे बुखार-खांसी के लक्षण के साथ आ रहे ओपीडी में, 2 माह से 2 साल की आयु तक खतरा ज्यादा

भोपाल (नप्र)। अचानक तेज बारिश, अगले दिन कड़ी धूप और फिर उमस... राजधानी का मौसम लगातार करवट ले रहा है। बारिश से गंदगी और दूषित पानी की समस्या भी बढ़ी है। यही कारण है कि इन दिनों वायरस और बैक्टीरिया दोनों सक्रिय हो गए हैं। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एम्स, हमीदिया और जेपी अस्पताल की ओपीडी में सोमवार और मंगलवार को ही 20 हजार से ज्यादा मरीज पहुंचे। जो बीते सप्ताह की तुलना में करीब 4 हजार अधिक है।

बच्चों पर ज्यादा असर

सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। जेपी अस्पताल में बाल रोगी ओपीडी में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पियूष पंचरत्न ने बताया कि सामान्य दिनों में रोजाना औसतन 80 बच्चे ओपीडी में आते हैं। अब यह संख्या 150 के करीब पहुंच गई है। इनमें वायरल के साथ बैक्टीरियल इंफेक्शन भी है। लगभग 7-8 फीसदी बच्चों को गंभीर स्थिति में भर्ती करना पड़ रहा है। जिन्हें सांस लेने में तकलीफ या पसली चलने जैसी समस्या होती है। इसका प्रमुख कारण रेस्पीरेट्री सिंसेशियल वायरस (आरएसवी) का एक्टिव होना है। इसके कारण बच्चों में फेफड़ों का इंफेक्शन देखने को मिल रहा है। इधर, मंगलवार को एम्स भोपाल में 15 साल से कम आयु के 723 मरीज बाल रोग विभाग की ओपीडी में पहुंचे। हमीदिया अस्पताल में यह संख्या 576 रही।

जबलपुर-रतलाम समेत 23 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट

नर्मदापुरम में तवा डैम के 5 गेट खोले, इंदौर में बारिश के बाद मकान गिरा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के जबलपुर, रतलाम समेत 23 जिलों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट है। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में हल्की बारिश होने के आसार हैं। भोपाल में सुबह से रुक-रुककर पानी गिर रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 में से 5 गेट 5-5 फीट तक खोले गए हैं। इनसे 43,010 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून टर्फ, डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की एक्टिविटी होने से मध्यप्रदेश में अगले चार दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी।

मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 25 से अधिक जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर चला। सबसे ज्यादा पानी इंदौर में 3.1 इंच गिर गया। रायसेन में 2.7 इंच, उज्जैन में 1.2 इंच और सिवनी में 1 इंच बारिश हुई। खरगोन, सीहोर, विदिशा, शाजापुर, आगर-मालवा, देवास, नर्मदापुरम, सागर, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा,

मंडला, उमरिया, खंडवा, नरसिंहपुर, गुना, ग्वालियर, बैतूल, दमोह में भी हल्की बारिश दर्ज की गई।

इधर, इंदौर में बुधवार को एक पुराना मकान अचानक भरभराकर गिर गया। मकान पिछले कुछ महीनों से खाली पड़ा था। हादसा जवाहर मार्ग से चंद्रभागा जूनी इंदौर की ओर जाने वाले लिंक रोड पर हुआ। अचानक हुए इस हादसे से आसपास के लोग घबरा गए। घटना की जानकारी मिलते ही रावजी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

दंपत्ति को 13 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 50 लाख ठगे

बैंक भेजकर एफडी तुड़वाई, 70 हजार में जमानत दी ; बुजुर्ग बोले- जिंदगीभर की कमाई ले गए

खंडवा (नप्र)। तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद सायबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला खंडवा के पंधाना नगर का है। जहां बुजुर्ग दंपत्ति को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 50 लाख रुपए ठग लिए। इतनी बड़ी ठगी के लिए सायबर ठग ने बुजुर्ग को बैंक भेजकर एफडी तक तुड़वा दी। बाद में 70 हजार रूपए अलग से लेकर जमानत भी दें दी। खुलासा तब हुआ जब जन्माष्टमी पर महिला अपने मायके गई और भाई को पूरी आपबीती सुनाई।

पीड़ित दंपत्ति के अनुसार उनकी पंधाना में बर्तनों की दुकान हैं। उनके बच्चे नहीं है, घर में दोनों अकेले रहते हैं। 18 जुलाई को उनके मोबाइल नंबर पर मुंबई के कोलंबा थाने से फोन आया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम कोलंबा थाने से बोल रहे हैं। आपके इस नंबर वाली सिम से हत्या, अपहरण और धोखाधड़ी की गई। फिर कहा कि

मामला काफी गंभीर है। आपके खिलाफ जांच होगी, जिसमें आपको सहयोग करना होगा।

ठगों ने पुलिस बनकर जांच के नाम पर घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। कहा कि हमारे अलावा किसी का फोन नहीं उठाना है। दंपती के मुताबिक, उनके पास पहली बार इस तरह का कॉल आया था। वे काफी डर गए थे और उनकी बात मानते चले गए।

पेंमेंट की जांच करने के नाम पर एफडी तुड़वाई- बुजुर्ग दंपती ने बताया कि ठगों ने हमें वीडियो कॉल किए, जिसमें पूरा थाना और वर्दी पहना हुआ पुलिस स्टाफ भी दिखाई देता था। ठगों ने कहा कि यदि आप घर में नहीं रहोगे तो आपको कोलंबा थाने आना पड़ेगा। दंपती ने कहा कि हम बुजुर्ग है, इतनी दूर कैसे आएंगे। इस पर ठगों ने उन्हें घर ही रहने की बात कहीं। इसके बाद 21 जुलाई को कहा कि आपके रुपयों की भी जांच करनी पड़ेगी। आप बैंक जाओ और अपनी एफडी तुड़वाकर हमारे खाते में ट्रांजेक्शन कर दो। दंपती ने 30 लाख रुपए की एफडी 21 जुलाई को तुड़वाकर ठगों के द्वारा दिए गए खाते में डाल दी।

एफडी तुड़वाने के लिए बोले- मैनेजर को कहना प्रापर्टी खरीदी

दंपती के अनुसार एक बार एफडी तुड़वाने के बाद ठगों ने 25 जुलाई को फिर से बैंक भेजा। बैंक में किसी को शंका न हो, इसलिए ठगों ने दंपती से कहा कि बैंक मैनेजर पूछे तो कहना हमने प्रापर्टी खरीदी है, इसके लिए पेंमेंट की जरूरत है। ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा 19 लाख 50 हजार की एफडी तुड़वा दी। पूरा पेमेंट अपने खाते में आरटीजीएस करवा लिया। इसमें ठगों का एक अकाउंट हैदराबाद और एक चंड़ीगढ़ का था।

जमानत देने आए डीएसपी साहब ने 70 हजार रूपए लिए

दंपती ने बताया कि हमारी जिंदगी भर की कमाई ठगने के बाद ठगों का फिर फोन आया। इस बार वीडियो कॉल पर डीएसपी साहब थे। डीएसपी साहब ने कहा कि देखो आप बुजुर्ग हो और इस तरह फंस गए हो, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास जो भी रुपए बचे हो, उसके बारे में बता दो।

अब रात में भी चलेंगे बिना ड्राइवर वाले ट्रक

इंसानों से 11 सेकंड पहले देख लेंगे कोई भी खतरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब ऑटोनॉमस व्हीकल्स की कल्पना की जा रही है। सिर्फ कल्पनी ही नहीं ऑटोनॉमस व्हीकल्स यानी कि बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों, को सड़कों पर उतारने की तैयारी भी चल रही है। कई कंपनियां ऑटोनॉमस व्हीकल्स पर काम कर रही हैं और इसी में एक नाम अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरोरा इनोवेशन का है। हाल ही में इस कंपनी बिना ड्राइवर के चलने वाले ट्रकों की शुरुआत करके इतिहास रच दिया था। अब इस कंपनी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। कंपनी ने दावा किया है कि उनके बिना ड्राइवर के चलने वाले ट्रक रात में भी हाईवे और सड़कों पर आसानी से चल सकते हैं। दिन

और रात, दोनों समय में चलने की क्षमता इन ट्रकों को लंबी दूरी तक यात्रा करने में मदद करेगी। इससे उन्हें उन नियमों से छुटकारा मिल जाएगा, जो इंसान ड्राइवरों पर लागू होते हैं। वर्तमान में एक ड्राइवर को 14 घंटे की अवधि में सिर्फ 11 घंटे तक ही ट्रक चलाने की अनुमति है। लंबी दूरी की यात्रा के बाद उन्हें 10 घंटे का आराम लेना अनिवार्य है। सेल्फ-ड्राइविंग ट्रक सर्विस शुरू करने वाली कंपनी ऑरोरा इनोवेशन के सीईओ क्रिस अर्म्सन ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह तकनीक 600 मील (लगभग 965 किमी) से ज्यादा की दूरी के लिए बहुत फायदेमंद है। अर्म्सन के मुताबिक रात में गाड़ी चला पाने की क्षमता आंशिक रूप से उनके लॉन्ग-रेंज लिडार सिस्टम के कारण है, जो अंधेरे में भी 450 मीटर (लगभग 1,500 फीट) से ज्यादा दूरी पर वस्तुओं का पता लगा सकता है। यह लिडार इंसानी ड्राइवर की तुलना में 11 सेकंड पहले ही वाहनों, पैदल चलने वाल लोगों और कचरे की पहचान कर सकता है।

अहमदाबाद के प्राइवेट स्कूल में 10वीं के छात्र की हत्या, बवाल

● 8वीं कक्षा के छात्र ने दिया वारदात को अंजाम, स्कूल में जमकर कोहराम

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के अहमदाबाद में सेवेंथ डे स्कूल में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने 10वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात मंगलवार दोपहर की है। देर शाम अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए करीब 2 हजारों लोगों की भीड़ ने बुधवार सुबह स्कूल का घेराव कर जमकर तोड़फोड़ की। प्रिंसिपल समेत पूरे स्टाफ को पीटा। सिंधी समुदाय के लोग, बजरंग दल, विहिप और एबीवीपी के कार्यकर्ता बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचते ही लोगों ने पहले तो स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़

शुरू कर दी। इसके बाद रेलिंग कूदकर स्कूल के अंदिर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही लोगों ने गार्ड, बस ड्राइवर्स को पीटना शुरू कर दिया।

अमेरिकी टैरिफ से मुकाबले के लिए साथ आया रूस

● बोला-भारतीय सामान का स्वागत है, हम तेल भी देंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ के बीच रूस का बड़ा बयान है। रूस का कहना है कि यदि किसी देश में भारतीय उत्पादों पर रोक लग रही है तो रूस के बाजार में उनका स्वागत है। भारत में रूसी मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बाबूश्किन ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अर्थव्यवस्था को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया

है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि दोस्त कभी पाबंदियां नहीं लगाते। रूस कभी इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने हमेशा कठिन समय में सहयोग कायम रखा है। हम भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखेंगे और इसके लिए मेकेनिज्म तैयार किया है। एससीओ में पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी।

एक-एक इंच पर चर्चा

अब एलएसी पर शांति के लिए भारत-चीन के बीच हुई बड़ी बात

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। इससे पहले भारत और चीन ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। ये कदम एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिरता लाने में मदद करेंगे। दोनों देशों ने

मिलकर कुछ नए तरीके खोजे हैं जिनसे सीमा पर हालात सामान्य बने रहें। भारत और चीन के अधिकारियों ने मिलकर बातचीत की। इसमें तय हुआ कि कुछ एक्सपर्ट ग्रुप, वर्किंग ग्रुप और जनरल लेवल मैकेनिज्म बनाए जाएंगे। ये ग्रुप सीमा पर होने वाली समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही चीन जाने वाले हैं। वहां वे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उनकी यात्रा से पहले ही दोनों देशों ने व्यापार को शुरू करने का फैसला किया है।

अपनी वायुसेना को मिलेंगे 97 एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट

● 62 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना के लिए 97 एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट खरीदने के लिए 62 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि एक हाई लेवल मीटिंग में फाइटर जेट की खरीद को अंतिम मंजूरी दे दी गई। इससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इन एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए ऑर्डर मिलने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है, क्योंकि मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एचएएल के सुधार पर जोर दे रहे हैं। मोदी सरकार के दौरान एचएएल को सभी तरह के स्वदेशी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और उनके इंजन बनाने के ऑर्डर मिले हैं। एचएएल को एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट के लिए यह दूसरा ऑर्डर होगा। इससे पहले सरकार एचएएल को 83 एयरक्राफ्ट्स बनाने का ऑर्डर दे चुकी है। एलसीए मार्क 1ए, तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियॉनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं।

सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

ज़िला चिकित्सालयों की क्षमता का होगा उन्नयन

बैतूल में पीपीपी मोड पर बनेगा मैडिकल कॉलेज, यूजी और पीजी कोर्स होंगे संचालित

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में बैतूल जिले में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कार्यों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय का प्रशासन एवं नियंत्रण शासन के पास ही रहेगा, वहीं निजी भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार सुनिश्चित होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने शासन द्वारा शीघ्र भूमि आवंटन एवं अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि कार्य तुरंत प्रारंभ किया जा सके। बैठक में विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक भैंसदेही श्री महेन्द्र सिंह चौहान, विधायक मुलताई श्री चन्द्रशेखर देशमुख, प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव, आयुक्त श्री तरुण राठी, आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुनील कपूर सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी आरकेडीएफ ग्रुप के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पीपीपी मॉडल पर स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। लगभग 25 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत जिला अस्पताल बैतूल का उन्नयन कर उसकी क्षमता 300 बैड से बढ़ाकर 675 बैड की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल एवं स्टाफ के लिए आवासीय परिसर का निर्माण भी किया जाएगा। कैथलैब, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी आधुनिक विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध होंगी। जिला अस्पताल में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

स्थानीय समस्याओं का प्राथमिकता से किया जाएगा समाधान: विधायक श्री खंडेलवाल- विधायक श्री हेमन्त खण्डेलवाल ने कहा कि कार्य प्राथमिकता पर शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि जिले के नागरिकों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान तत्काल शासन-प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुनील कपूर ने कहा कि निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जाएगा, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ हो सकें।

मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण अस्पताल बैतूल की स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों के अनुरूप की जाएगी। आरकेडीएफ समूह जिला चिकित्सालय का उन्नयन कर उसे 675 बैड क्षमता वाले शिक्षण अस्पताल में विकसित करेगा। वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं में कोई व्यवधान उत्पन्न किए बिना अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। एमबीबीएस एवं एमडी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आरकेडीएफ समूह आवश्यक निवेश करेगा और पर्याप्त संकाय, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

आरकेडीएफ समूह परियोजना प्रारंभ होने के 90 दिनों के भीतर शासन को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें निर्माण और उन्नयन की समयसीमा, डिज़ाइन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया एवं लागत का संपूर्ण विवरण शामिल होगा। आरकेडीएफ समूह द्वारा अस्पताल और कॉलेज में आधुनिक उपकरणों एवं नवीनतम तकनीकी प्रगति का उपयोग करते हुए सेवाओं को समय-समय पर अद्यतन रखा जाएगा और हर तिमाही शासन को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। निर्धारित समयसीमा में शिक्षण अस्पताल को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा। परियोजना के संचालन में बायो-मैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

आरिफ मसूद पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज

फर्जी दस्तावेज लगाकर कॉलेज की मान्यता लेने का मामला; हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोहेफिजा थाने में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाई।

यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने एफआईआर की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, छात्रों के हित को देखते हुए कोर्ट ने कॉलेज को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन नए एडमिशन पर पूरी तरह रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज नहीं चल सकता।

कोर्ट ने कहा था- 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करें- हाईकोर्ट ने सोमवार को फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता प्राप्त करने के मामले में सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को आदेश दिया कि वे तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर इसकी जानकारी कोर्ट को दें। जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कॉलेज की मान्यता ली थी। कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

कॉलेज की संचालन समिति में सचिव हैं आरिफ मसूद

इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन अमन एजुकेशन सोसाइटी करती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इस सोसाइटी के सचिव हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भोपाल के खानूगांव में स्थित है।

एसआईटी करेगी मामले की जांच

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की अब एसआईटी जांच करेगी। एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 90 दिन में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें। बता दें कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन छात्र हित को देखते हुए कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने सालों तक कॉलेज नहीं चल सकता था।

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने की थी शिकायत

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने माना कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन के लिए फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी और मान्यता ली। इसके बाद कॉलेज की मान्यता रद्द की गई। जांच में पता चला कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए सेल डीड तैयार करवाई और इसे पंजीयन कार्यालय में फर्जी तरीके से दर्ज भी बताया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर ने की सौजन्य भेंट

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर ने सपत्नीक सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का क्रिकेटर श्री अय्यर ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वह इंदौर शहर के निवासी हैं। भेंट के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री अय्यर को उनके अब तक के क्रिकेट प्रदर्शन की बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को खून से खत लिखा

भोपाल कांग्रेस शहर अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध; पूर्व शहर अध्यक्ष ने आत्मदाह की धमकी दी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में 16 अगस्त को नियुक्त किए गए 71 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेशभर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। भोपाल कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना 'मोनू' ने मंगलवार को भोपाल के बिट्टन मार्केट चौराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने खून से पत्र लिखकर राहुल गांधी से न्याय की मांग की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए।

प्रदर्शन के दौरान मोनू सक्सेना ने कहा कि भोपाल के नए जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना को लेन-देन के जरिए पद दिया गया है। उनका यह भी आरोप है कि प्रवीण सक्सेना के भाजपा नेताओं से भी संबंध हैं। मोनू सक्सेना ने ऐलान किया कि वे दिल्ली जाकर राहुल गांधी के सामने आत्मदाह की कोशिश करेंगे।

उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से कांग्रेस संगठन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता राहुल गांधी को अंधेरे में रखकर व्यापमं घोटाले के आरोपियों को संगठन में पद दे रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मोनू सक्सेना के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और आंदोलन को आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी।

डेढ़ करोड़ की डिफेंडर कार गिफ्ट करने का भी आरोप

भोपाल कांग्रेस के शहर अध्यक्ष के रूप में प्रवीण सक्सेना की नियुक्ति के बाद, मोनू सक्सेना पहले भी सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह पद पाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की कीमत वाली डिफेंडर कार गिफ्ट की गई थी। मोनू का दावा है कि वे जल्द ही इस मामले में सबूतों के साथ खुलासा करेंगे।

सरकारी स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कार्य उच्च गुणवत्तापूर्ण हो

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने पाठ्य पुस्तक निगम की गवर्निंग बॉडी की बैठक ली

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित की जाने वाली किताबें उच्च गुणवत्ता की हों। उन्होंने कहा कि मुद्रण कार्य से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय समय-सीमा में पूरी की जायें। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों का वितरण शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही पूरा किया जाये। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह बुधवार को मंत्रालय में पाठ्य पुस्तक निगम की गवर्निंग बॉडी की बैठक ली। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता, वित्त, माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

बैठक में पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी श्री विनय निगम ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में करीब 9 करोड़ पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण होगा। इसके लिये ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत निविदा की प्रक्रिया होगी। निगम शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 10 मार्च 2026 तक सभी पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कार्य पूरा कर लेगा। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष अप्रैल 2025 में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू किया गया था। इस वर्ष अब तक लगभग सभी पाठ्य पुस्तकों का वितरण विद्यार्थियों को किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि निगम ने कुछ सरकारी स्कूलों को खेल-कूद मैदान, अतिरिक्त कक्ष और नवीन कक्ष निर्माण के लिये अनुदान राशि मंजूर की है।

किताबों की पांडुलिपि डेढ़ माह में मिलेगी

बैठक में भी बताया गया कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र के लिये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से किताबों की पांडुलिपि सितंबर 2025 अंत तक पाठ्य पुस्तक निगम को उपलब्ध करा दी जायेंगी। मध्यप्रदेश, देश के उन चुनिंदा राज्यों में है, जहां बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सत्र शुरू होते ही वितरित की गयीं।

स्थानीय भाषा में सामग्री विकास

स्कूल शिक्षा विभाग ने 8 स्थानीय भाषाओं- बुन्देली, बघेली, मालवी, निवाड़ी, गोंडी, भीली, बारेली और कोरकू भाषाओं में सामग्री का विकास किया है। विभाग का यह प्रयास बच्चों में स्थानीय भाषा के प्रति लगाव के उद्देश्य से किया गया है।

अर्चना बोली- कॉन्स्टेबल राम तोमर कॉल-मैसेज कर तंग करता था

सारांश को करीबी दोस्त बताया; कहा- हरदा में ढाबे में बैठकर भागने की प्लानिंग की

भोपाल (नप्र)। नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से गायब हुई एडवोकेट अर्चना तिवारी को 13 दिन बाद बुधवार को सकुशल बरामद कर जीआरपी ने परिजन के सुपुर्द कर दिया। इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी कटनी में छात्र नेता भी रही है। बरामदगी के बाद पुलिस को दिए बयान में उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

अर्चना ने पुलिस को बताया कि ग्वालियर का कॉन्स्टेबल राम सिंह तोमर उसे लगातार कॉल कर परेशान करता था। वह उसे जबलपुर से जानती है, तब वहां प्रैक्टिस करती थी। राम भी वहीं था और कई केस उसके पास लाया करता था। जबलपुर छोड़ने के बाद भी राम तोमर उसे लगातार कॉल और मैसेज कर तंग करता था।

अर्चना ने शुजालपुर के सारांश जोगचंद्र को करीबी दोस्त बताया है। उसी ने अर्चना की लापता रहने के दौरान सबसे अधिक मदद की। बयान से ये भी पता चला कि सारांश उस दिन अर्चना के साथ ट्रेन में था। हालांकि पहले अर्चना ने बताया था कि सारांश को उसने शुजालपुर से इटारसी बुलाया था। अर्चना ने बताा कि इसी महीने के पहले हफ्ते में उसने सारांश के साथ हरदा में ढाबे में बैठकर बात की और भागने कि प्लानिंग बनाई थी।

अर्चना बोली- पढ़ाई छोड़ने का दबाव बनाते थे परिजन- एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि जांच में पता चला है कि अर्चना तिवारी की

शुजालपुर के रहने वाले सारांश जोगचंद्र से इंदौर में दोस्ती हुई थी। दोनों एक ही ट्रेन में उस दिन (7 अगस्त) यात्रा कर रहे थे। सारांश ने अर्चना से कुछ लीगल एडवाइज ली थी।

घरवालों ने एक पटवारी के साथ अर्चना का रिश्ता तय किया था। परिजन उस पर पढ़ाई छोड़कर शादी का दबाव बना रहे थे। इसी महीने के पहले हफ्ते में अर्चना ने सारांश से हरदा में ढाबे में बैठकर बात की और भागने कि प्लानिंग बनाई। हालांकि बाद में भागने की प्लानिंग कैंसिल कर गुमशुदगी की साजिश रची।

सोचा था जीआरपी मिसिंग केस पर ध्यान नहीं देगी- अर्चना तिवारी को लगा था कि जीआरपी मिसिंग केस पर इतना ध्यान नहीं देगी। वह ऐसी जगह से भागने की प्लानिंग बनाई जहां पर सीसीटीवी न हो। नर्मदापुरम निवासी तेजेंदर सिंह ने अर्चना को नर्मदापुरम में ट्रेन में कपड़े दिए।

अर्चना बी-3 कोच से ए-2 कोच में जाकर आउटर से बाहर निकल गई। वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं था। उसने तेजेंदर को बागतवा के जंगलों में मोबाइल फेंकने को कहा। इसके बाद अर्चना सारांश के साथ कार से चली गई। उसी रात चोरी के एक मामले में तेजेंदर को दिल्ली पुलिस ले गई।

ट्रेन में सामान छोड़ा, ताकि लगे कि कहीं गिर गई है- अर्चना ने जानबूझकर ट्रेन में समान छोड़ा ताकि पुलिस को लगे कि अर्चना कहीं गिर गई है। मोबाइल भी जंगल के पास बंद हुआ। सारांश से वह वॉट्सऐप कॉल पर बात करती थी। इसलिए पुलिस को सीडीआर नहीं मिला। सारांश को जब पुलिस ने उठाया तो मामले की परतें खुलने लगीं। दोनों ने यात्रा के दौरान टोल को भी अवॉइड किया। अर्चना 12 दिन तक कहां-कहां रही...?

पहले हैदराबाद गई, फिर नेपाल जाने की प्लानिंग की- मामले के तूल पकड़ने के बाद अर्चना ने दूसरे राज्यों में जाने की प्लानिंग की। वह पहले हैदराबाद गई, फिर नेपाल जाने की प्लानिंग की। वह बस के जरिए दिल्ली होते हुए काठमांडू चली गई। सारांश वापस आ गया था। उसने जानबूझकर अपना मोबाइल इंदौर में छोड़ रखा था।

सारांश को राउंडअप करने के बाद अर्चना को बॉर्डर तक बुलाकर पुलिस ने बरामद किया। फिर दिल्ली के रास्ते बुधवार (20 अगस्त) को फ्लाइट से उसे भोपाल लेकर आई।

फॉरच्यून प्राइड सिटी कॉलोनी का गेट तोड़ने पहुंची निगम टीम, विरोध

फॉरच्यून प्राइड सिटी में सड़क पर उतरे लोग; कहा- कार्रवाई गलत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के त्रिलंगा स्थित फॉरच्यून प्राइड सिटी कॉलोनी में बुधवार को कई लोग विरोध में सड़क पर उतर गए। यहां नगर निगम की टीम कॉलोनी का मुख्य गेट तोड़ने पहुंची थी। लोगों का कहना था कि बिना नोटिस और समय दिए कार्रवाई की जा रही है, जो गलत है।

त्रिलंगा ई-8 में फॉरच्यून प्राइड सिटी है। कवर्ड कैम्पस की इस कॉलोनी में 50 से अधिक घर है। मुख्य रास्ते पर गेट बना है। इसे अवैध बताते हुए बुधवार दोपहर 12 बजे निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची। इसी दौरान कई महिला-पुरुष विरोध में उतर गए।

कार्रवाई से पहले नोटिस भी नहीं दिया

करीब दो घंटे से कॉलोनी के लोग विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि गेट तोड़ने से पहले न तो नोटिस मिला और न ही समय दिया गया। मंगलवार को निगम की टीम जरूर आई थी। कहा था कि बुधवार को कार्रवाई करेंगे। हम समय चाहते हैं। ताकि, मामले का उचित निराकरण हो सके।

भोजपुर रोड के लिए 1100 पेड़ काटे, बारिश बाद बनेगी

50 करोड़ रुपए से फोरलेन बनेगा; होटल-दुकानों के लिए पेड़ों की अवैध कटाई

भोपाल (नप्र)। भोपाल की 11 मिल से बंगरसिया तक (भोजपुर रोड) 6 किमी सड़क 50 करोड़ रुपए से टू-लेन से फोरलेन में बदलेगी। इसके लिए करीब 1100 पेड़ काटे जा रहे हैं। फोरलेन की जद में करीब 100 पेड़ और आ रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की रोक के बाद इन्हें बचाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के ने बताया, पेड़ों को बचाते हुए सड़क बनाएंगे।

बारिश के बाद सड़क निर्माण शुरू होगा। एक साल के अंदर सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि, फोरलेन किनारे कई लोग दुकान और होटलों के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करने के मूड में है।

एफडीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

पीडब्ल्यूडी अफसरों की माने तो यह सड़क प्रदेश में एक मॉडल बनेगी। इस सड़क में एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि मौजूदा सड़क के मटेरियल को रीयूज किया जाएगा।

यह है एफडीआर टेक्नोलॉजी

फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) एक रिसाइक्लिंग पद्धति है, जिसमें कम संसाधनों में टिकाऊ सड़कें बनाई जाती हैं। खराब हो चुकी पक्की सड़क को उखाड़कर उससे निकले मटेरियल में केमिकल मिलाया जाता है, जिससे नया मटेरियल तैयार किया जाता है। इसे फिर सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। इससे लागत भी कम आती है।

सड़क की स्थिति खराब, परेशान होते हैं श्रद्धालु

वर्तमान में 11 मिल से बंगरसिया तक की सड़क की हालत काफी खराब है। यह सड़क धार्मिक नगरी भोजपुर को जोड़ती है। हर रोज हजारों लोग इस खराब सड़क से गुजरने के कारण परेशान होते हैं। बारिश के चलते सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं।

हर साल होता है भोजपुर महोत्सव

भोजपुर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहां हर साल भोजपुर महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें देश-विदेश के कवि, साहित्यकार और टीवी-फिल्म कलाकार शामिल होते हैं। हालांकि, 6 किमी लंबी सड़क के गड्ढे उन्हें परेशान कर देते हैं। यही समस्या श्रद्धालुओं के साथ भी होती है।

कई जिलों का रास्ता भी

11 मिल से बंगरसिया तक सड़क बनने से रायसेन, विदिशा, बैतूल समेत कई जिलों के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

संपादकीय

राजपूत-मराठा विवाद?

क्या राजपूत राजाओं पर मराठाओं का कभी सीधा नियंत्रण था? क्या मराठों ने राजस्थान के राजाओं पर भी शासन किया था और क्या मराठाओं और राजपूतों में कभी लड़ाइयां हुई थीं? ये तमाम सवाल हाल में एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब के तीसरे अध्याय में एक मानचित्र को लेकर हो रहे विवाद से उठे हैं। इस नक्शे में 1759 में मराठा साम्राज्य की सीमा में जैसलमेर रियासत को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। इसको लेकर जैसलमेर रियासत के वंशजों और नागपुर के भोसले परिवार के वंशजों ने परस्पर विरोधी दावे किए हैं। यह विवाद सुलगने पर एनसीईआरटी ने इस मामले में एक समिति बनाने की घोषणा की है। यह समिति उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त सुझावों की जांच करेगी और सिफारिशें देगी। हालांकि जैसलमेर को मराठों के अधीन बताने को लेकर इतिहासकारों की राय भी बंटी हुई है। किताब में छपे मानचित्र के अनुसार, मराठा साम्राज्य मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था। इसमें पाकिस्तान के अटक और पेशावर तक का क्षेत्र भी शामिल दिखाया गया है। जबकि जैसलमेर राजपरिवार के वंशज चैतन्य राज सिंह ने इस मानचित्र पर आपत्ति जताते हुए इसे ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर रूप से आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अपुष्ट और ऐतिहासिक साक्ष्यविहीन जानकारी न केवल एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और जनभावनाओं को भी आघात पहुंचाती है। यह हमारे पूर्वजों के बलिदान, संप्रभुता और शौर्यगाथा को धूमिल करने का प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। दूसरी तरफ नागपुर के भोसले परिवार के वंशज राजे मुधोजी भोसले ने इस मानचित्र के समर्थन में ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के कुछ राजपरिवार मराठा साम्राज्य के इस नक्शे को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम मराठा साम्राज्य का विरोध करने वालों की निंदा करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या राजस्थान के राजपूत राजा मराठा शासकों के अधीन थे? इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य दो प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित था। 'कामाविशी' और 'सरंजामी।' शिवाजी महाराज का मूल स्वराज्य 'कामाविशी' क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें पुणे, पश्चिमी महाराष्ट्र और कर्नाटक का एक छोटा-सा हिस्सा शामिल था। दूसरा भाग 'सरंजामी' (सामंती) क्षेत्र था। इसमें शिंदे, होल्कर, गायकवाड़, भोसले जैसे सरदारों के नियंत्रण वाले इलाक़े शामिल थे। ये क्षेत्र पेशवाओं के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसी संदर्भ में दिल्ली विवि में इतिहास के प्रोफेसर अनिरूद्ध देशपांडे का कहना है कि मराठा चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूलते थे। मराठा सरदारों को राजपूत अपने आंतरिक विवादों मे हस्तक्षेप के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में आमंत्रित जरूर करते थे। जबकि वरिष्ठ इतिहासकर जयसिंहराव पवार का कहना है कि मराठों ने राजपूतों पर शासन किया। वे मुग़ल सम्राट से हुए समझौते के तहत ऐसा कर रहे थे। मराठों ने राजस्थान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और 'ट्रिब्यूट' (एक प्रकार का कर) वसूला था। राजपूत राजाओं और मराठा शासकों के बीच आर्थिक संबंधों की प्रकृति 1752 में मुग़लों और मराठों के बीच हुई 'अहमदनामा' संधि पर आधारित थी। चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर, मराठों के राजनीतिक प्रभुत्व का सबूत माने जाते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जैसलमेर रियासत ने कभी ऐसा कर दिया हो। बहरहाल इस विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। इतिहास के रूप में वही पढ़ाया जाना चाहिए, जो 'ऐतिहासिक रूप से सही व प्रामाणिक हो'।

लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया पर एआई का शिकंजा

एआई-संचालित बॉट्स और स्वचालित अभियान लोकतंत्र के लिए एक और गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। ये बॉट्स झूठी सूचनाओं को बिजली की गति से फैलाते हैं और कृत्रिम जन समर्थन का भ्रम रचते हैं। 2024 के भारतीय लोकसभा चुनाव में, एक्स पर वायरल हुए डीपफेक वीडियो और भ्रामक मीम्स ने मतदाताओं के बीच भारी भ्रम और अविश्वास को जन्म दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 64 देशों के चुनावों में एआई-जनित सामग्री ने जनमत को गहरे रूप से प्रभावित किया। ये बॉट्स न केवल सूचना तंत्र को दूषित करते हैं, बल्कि सामाजिक ध्रुवीकरण और अविश्वास को बढ़ावा देकर लोकतंत्र की एकता और अखंडता को चूर-चूर करते हैं।

नजरिया

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'
लेखक प्राध्यापक हैं।

लोकतंत्र का मूलभूत आधार खतरे में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जो कभी मानव प्रगति का स्वर्णिम प्रतीक थी, अब उसी लोकतंत्र की नींव को खोखला करने का हथियार बन चुकी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जो जनता की सच्ची आवाज को सत्ता के शिखर तक ले जाते हैं, अब एआई-जनित डीपफेक, भ्रामक समाचारों और माइक्रो-टारगेटिंग के जाल में फंस चुके हैं। यह तकनीक न केवल मतदाताओं के मन को चुपके से प्रभावित कर रही है, बल्कि उनकी स्वतंत्र इच्छा को बंधक बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही अपहरण कर रही है।

एआई की असाधारण शक्ति इसके डेटा विश्लेषण और वैयक्तिकृत सामग्री सृजन की क्षमता में निहित है। एक्स, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों पर कार्यरत एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि आपको क्या देखना है। ये एल्गोरिदम आपकी उम्र, रुचियों और राजनीतिक झुकाव का गहन विश्लेषण कर ऐसी सामग्री परोसते हैं, जो आपके विचारों को सूक्ष्म रूप से ढाल देती है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा 87 मिलियन फेसबुक उपयोगकर्ताओं के डेटा के दुरुपयोग का उदाहरण इसका जीवंत प्रमाण है। इस डेटा के आधार पर माइक्रो-टारगेटेड विज्ञापनों ने अनिर्णीत मतदाताओं को प्रभावित किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, इस हेरफेर ने 2-5 प्रतिशत मतदाताओं के व्यवहार को बदला, जो एक अत्यंत करीबी चुनाव में निर्णायक सिद्ध हुआ। यह हेरफेर इतना परिष्कृत और सूक्ष्म है कि मतदाता को इसका आभास तक नहीं होता, फिर भी यह उनके निर्णयों को गुप्त रूप से नियंत्रित करता है।

डीपफेक तकनीक ने लोकतंत्र के लिए खतरे को और भी भयावह बना दिया है। एआई-जनित नकली वीडियो और ऑडियो इतने जीवंत और विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि सामान्य व्यक्ति उन्हें वास्तविकता से अलग करने में असमर्थ रहता है। 2024 के रोमानिया राष्ट्रपति चुनाव में एक डीपफेक ऑडियो, जो रूस-समर्थित प्रभाव अभियान का हिस्सा था, ने पहले दौर के मतदान को रद्द करने के लिए बाध्य किया। इसी तरह, 2023 में स्लोवाकिया के एक चुनाव में डीपफेक ऑडियो ने एक उम्मीदवार की छवि को कलंकित कर जनता का विश्वास तोड़ा। मिशिगन विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार, 64 प्रतिशत लोग डीपफेक को पहली नजर में वास्तविक मान लेते हैं। ये घटनाएँ न केवल उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा को नष्ट करती हैं, बल्कि मतदाताओं के सत्य तक पहुँचने के मूलभूत अधिकार को ही कुचल देती हैं।

एआई-संचालित बॉट्स और स्वचालित अभियान लोकतंत्र के लिए एक और गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। ये बॉट्स झूठी सूचनाओं को बिजली की गति से फैलाते हैं और कृत्रिम जन समर्थन का भ्रम रचते हैं। 2024 के भारतीय लोकसभा चुनाव में, एक्स पर वायरल हुए डीपफेक वीडियो और भ्रामक मीम्स ने मतदाताओं के बीच भारी भ्रम और अविश्वास को जन्म दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 64 देशों के चुनावों में एआई-जनित सामग्री ने जनमत को गहरे रूप से प्रभावित किया। ये बॉट्स न केवल सूचना तंत्र को दूषित करते हैं, बल्कि सामाजिक ध्रुवीकरण और अविश्वास को बढ़ावा देकर लोकतंत्र की एकता और अखंडता को चूर-चूर करते हैं।

माइक्रो-टारगेटिंग के माध्यम से एआई व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कर मतदाताओं के मन को गुप्त रूप से नियंत्रित करता है, उनकी स्वतंत्र इच्छा को हथियार बना लेता है। 2022 के ब्राजील चुनाव में एक डीपफेक वीडियो, जिसमें एक पत्रकार को गलत पोल परिणाम बताते दिखाया गया, ने लुला के समर्थकों के बीच भ्रम और अविश्वास की आंधी मचा दी। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2016 से 2024 तक 81 देशों में एआई-संचालित प्रचार अभियानों ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया। यह तकनीक मतदाताओं को केवल वही सामग्री दिखाती है, जो उनकी मौजूदा धारणाओं को मजबूत करती है या उन्हें चुपके से बदल देती है, जिससे निष्पक्ष सूचना का मूलभूत अधिकार नष्ट हो जाता है।

एआई ने गलत सूचना को एक खतरनाक हथियार में बदल दिया है, जो अब पहले से कहीं अधिक सस्ता और सहज हो गया है। जहाँ पहले जनमत को प्रभावित करने के लिए विशाल रैलियों और महंगे प्रचार अभियानों की आवश्यकता होती थी, वहीं अब महज कुछ हजार रुपये में सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान खड़ा किया जा सकता है। 2023 में भारत में एक जांच ने खुलासा किया कि डिजिटल एजेंसियाँ 10,000 रुपये से भी कम में वायरल अभियान चला सकती हैं, जो छोटे और कम संसाधन वाले दलों को नष्ट करने की ताकत रखता है। यह लोकतंत्र को तकनीकी और वित्तीय शक्ति के चंगुल में जकड़ रहा है, जिससे जनता की आवाज दबने का खतरा मंडरा रहा है।

लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य हैं, लेकिन एआई-आधारित प्रचार में ये गायब हैं। 2019 के यूरोपीय चुनाव में 53 प्रतिशतफेसबुक विज्ञापनों में प्रायोजक की जानकारी नहीं थी। यह 'अदृश्य प्रचार' निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है। इस खतरे से निपटने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं। पहला, सरकारों को डिजिटल प्रचार के लिए स्पष्ट नियम बनाना होगा। यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज एक्ट (2022) एक मिसाल है, जो सोशल मीडिया कंपनियों को गलत सूचना रोकने के लिए बाध्य करता है। भारत में भी ऐसे कानून चाहिए। दूसरा, हर डिजिटल विज्ञापन में प्रायोजक और उद्देश्य की जानकारी अनिवार्य हो। तीसरा, डिजिटल साक्षरता अभियान जरूरी हैं। भारत में केवल 38 प्रतिशत लोग ऑनलाइन सामग्री की प्रामाणिकता परख पाते हैं।

वैश्विक सहयोग इस संकट से निपटने की रीढ़ है, क्योंकि इंटरनेट की सीमाहीन प्रकृति के कारण किसी एक देश के नियम नाकाफी हैं। 2024 में रूस और चीन से संचालित परिष्कृत अभियानों ने अफ्रीकी और एशियाई देशों के चुनावों को अपने नापाक इरादों का शिकार बनाया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ खतरे में पड़ गईं। यूनेस्को की 'रेकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ एआई' (2021) जैसे वैश्विक ढांचे इस दिशा में सशक्त कदम हैं, जो एआई के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देते हैं। फिर भी, इन प्रयासों को और अधिक समन्वित और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की रक्षा हो सके।

हालाँकि, सबसे बड़ी ताकत जनता के जागरूक और विवेकपूर्ण मन में निहित है। तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत हो, लोकतंत्र का असली आधार नागरिकों की सूझबूझ और सजगता है। यदि नागरिक बिना सोचे-समझे सूचनाओं को स्वीकार करते रहेंगे, तो लोकतंत्र का ढाँचा चरमराने लगेगा। लेकिन यदि वे सवाल उठाएँ, तथ्यों की गहन जाँच करें और सच को झूठ से अलग करने का संकल्प लें, तो कोई भी एल्गोरिदम या कृत्रिम बुद्धिमत्ता उनकी स्वतंत्र इच्छा को दबा नहीं सकती। यह जागरूकता ही वह दीपक है, जो तकनीक के अंधेरे तूफान में लोकतंत्र की लौ को जलाए रखेगा।

एआई एक दोधारी तलवार है, यह मानवता के लिए अभूतपूर्व अवसरों का सृजनकर्ता है, मगर अनियंत्रित होने पर लोकतंत्र का काल बन सकता है। 2024 के वैश्विक चुनावों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि समय तेजी से हाथ से निकल रहा है। केवल सख्त कानून, पूर्ण पारदर्शिता और जागरूक नागरिकों का अटल संकल्प ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। यदि हम अब भी नहीं चेते, तो जनता की स्वतंत्र इच्छा एल्गोरिदम के ठंडे, यांत्रिक जाल में कैद होकर एक भयावह भ्रम बन जाएगी, और लोकतंत्र का स्वर्णिम स्वरूप हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा।

कृषि व्यापार : अवसर, जोखिम और संतुलन की चुनौती

भारत-अमेरिका संबंध

अरूण कुमार डनायक
लेखक गांधी विचारों के अध्येता व समाजसेवी हैं

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध लगातार व्यापक होने की संभावनाओं के बीच कृषि क्षेत्र इस साझेदारी का सबसे संवेदनशील और विवादास्पद हिस्सा बना हुआ है। अमेरिका लंबे समय से भारतीय कृषि बाजार में प्रवेश का दबाव बना रहा है, लेकिन भारत ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से अब तक इसे बड़े पैमाने पर विदेशी आयात से सुरक्षित रखा है। छोटे और सीमांत किसान, पारंपरिक पारिवारिक खेती के साथ, भारतीय कृषि की रीढ़ हैं।

भारत के कृषि क्षेत्र का महत्व केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि यह 70 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों के लिए आजीविका की वास्तविकताओं, अनिश्चितताओं के दौर में एक सहारा होने के साथ साथ घरेलू राजनीतिक प्राथमिकताओं से भी जुड़ा हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारस्तंभ कृषि हिस्सेदारी (2022-23) में सकल मूल्य वर्धन का 18.4 प्रतिशत है। यही कारण है कि राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र में समझौते की बहुत कम गुंजाइश रहती है।

वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका से 1.6 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद बादाम, पिस्ता, एथेनॉल, मक्का, कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अन्य पशु आहार सामग्री आदि आयात किए। इसी कालावधि में भारत ने अमेरिका को 45.7 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पाद जैसे चाय, कॉफी और मसाले, बासमती चावल, प्रसंस्कृत फल-सब्जियाँ, ऑर्गेनिक तथा समुद्री खाद्य उत्पाद, तिलहन और दलहन निर्यात किये। कृषि क्षेत्र में भारत का व्यापार संतुलन अधिशेष में है।

डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सहित अनेक विकासशील देशों के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण बदला है और वह तरह तरह के आर्थिक दबाव इन देशों पर डाल रहा है। राष्ट्रपति ट्रम्प का कहना है कि भारत के कृषि आयात पर औसत शुल्क 39 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह औसतन 5 प्रतिशत है। अमेरिका का तर्क है कि इन ऊँचे शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं (जैसे स्वच्छता व पौध-स्वास्थ्य मानक) से अमेरिकी उत्पादों को अनुचित रूप से रोका जाता है।

भारत ने आरंभ से ही अमेरिकी प्रशासन के साथ कूटनीतिक स्तर पर संवाद को प्राथमिकता दी और उसके आरोपों का संयमित व संतुलित उत्तर दिया। किंतु जब कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर वार्ता का गतिरोध समाप्त नहीं हो सका, तब घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों और नीतिगत सिद्धांतों के मद्देनज़र भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अपने कृषि क्षेत्र की सुरक्षा एक ऐसा राष्ट्रीय संकल्प है, जिस पर कोई समझौता संभव नहीं।

भारत का मानना है कि कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार के लिए अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए इसे विदेशी आयात से सुरक्षा मिलनी चाहिए। अमेरिका जैसे देशों की कृषि भारी सब्सिडी पर आधारित है-जिससे उनका उत्पादन लागत कृत्रिम रूप से कम होता है और वे सस्ते में निर्यात कर सकते हैं। भारत के विश्व व्यापार संगठन दायित्व उसे संवेदनशील क्षेत्रों में संरक्षण की अनुमति देते हैं, भारत अचानक आयात बढ़ने या कीमत गिरने पर शुल्क बढ़ा सकता है और भारत मौजूदा शुल्क इन्हीं सीमाओं के भीतर रखता है। इस समझौते के हो जाने के अनेक संभावित नुकसान हैं। भारत सरकार के नीति निर्माताओं का सोचना है कि अमेरिका के दबाव के चलते भारत सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुदान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे नीतिगत मामलों में कठोर व अलोकप्रिय फैसले लेने पड़ सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों व किसान नेताओं का मानना है कि सस्ते अमेरिकी आयात घरेलू बाजार में दाम गिरा सकते हैं। किसानों की आय में कमी के कारण छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित होंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा बढ़ने से स्थानीय व्यापारी और किसान बाजार से बाहर हो सकते हैं। इन प्रत्यक्ष प्रभावों के अलावा गैर-शुल्क बाधाएँ और उनके व्यापक प्रतिकूल असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह भावना सभी राजनीतिक दलों में समान रूप से गहराई से व्याप्त है, जिसके कारण किसी भी सरकार के लिए अपने रुख में बड़ा बदलाव करना राजनीतिक रूप से अत्यंत जोखिमपूर्ण और महंगा साबित हो सकता है।

ऐसा नहीं है कि भारत-अमेरिका कृषि व्यापार होने पर केवल नुकसान ही है। यदि दोनों देशों में समझौता हो जाता है तो इसके अनेक संभावित फायदे भी हैं। इसके फलस्वरूप निर्यात अवसरों में वृद्धि होगी, अमेरिका में भारतीय चाय, मसाले, समुद्री उत्पाद और ऑर्गेनिक फूड की माँग बढ़ सकती है। तकनीकी सहयोग बढेगा और आधुनिक मशीनरी, सिंचाई तकनीक, ड्रोन और सटीक कृषि पद्धतियों तक भारत की पहुँच मजबूत होगी। कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अमेरिकी निवेश से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा। भारतीय नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण व पोषक तत्वों से भरपूर कृषि उत्पाद उपलब्ध होंगे, उच्च मूल्य वाली एवं निर्यातोन्मुख फसलों की खेती को नया प्रोत्साहन मिलेगा, और अमेरिकी मानकों के अनुरूप उत्पादन से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को निर्णायक बढ़त हासिल होने की प्रबल संभावना बनेगी। हरित क्रांति के दौर में इंदिरा गांधी के दूरदर्शी निर्णय, कृषि मंत्री सी. सुब्रामनियम का सतत कार्यकाल और स्वामीनाथन जैसे प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों की सूझबूझ भरी सलाह के आधार पर अमेरिका के साथ हुई वार्ताएं, आज के भारत-अमेरिका कृषि व्यापार गतिरोध को समझने और सुलझाने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ के साथ आंशिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। तब सरकार ने अमेरिकी शर्तें स्वीकार तो कीं, किंतु अंतिम लक्ष्य कृषि आत्मनिर्भरता को ही बनाया। इसी संकल्प का परिणाम था हरित क्रांति, जिसने गेहूं और चावल की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि की और देश को खाद्यान्न संकट से उबार दिया। मोदी सरकार चाहे तो वाजपेयी सरकार की पूंजी निवेश सह अनुदान आधारित ग्रामीण भंडार योजना, मनमोहन सरकार की कृषि ऋण विस्तार व ऋण माफी नीतियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कृषि निवेश ऋण में योगदान जैसे उपायों से प्रेरणा लेकर कृषि सुधार कर सकती है। भारत और अमेरिका के कृषि समझौते में आर्थिक अवसर और तकनीकी सहयोग हैं, पर बड़े जोखिम भी जुड़े हैं। भारत को किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा का संरक्षण करते हुए अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पादों के मुकाबले घरेलू किसानों को सुरक्षा देनी होगी। विदेश व्यापार बढ़े, साथ ही घरेलू कीमतें स्थिर रहें। भारत सरकार को इस संतुलन को सावधानी से बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दीर्घकालिक रूप में विवेकपूर्ण नीति ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा और ग्रामीण स्थिरता दोनों सुनिश्चित कर सकती है।

युवा स्क्रीन एडिक्शन: एक मौन संकट

मुद्दा

संध्या अग्रवाल
लेखक साहित्यकार हैं।

आज के बच्चे और युवा जिस चुपचाप फैलते संकट से जूझ रहे हैं, उसका नाम है - स्क्रीन एडिक्शन। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और टीवी की चमकती स्क्रीन ने उनकी दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को जकड़ लिया है। यह कोई तात्कालिक शौक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे पनपती ऐसी आदत है जो आने वाले कल की पीढ़ी को कमजोर बना सकती है।

हम सबने देखा है - परिवार के किसी समारोह में भी बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, छात्र पढ़ाई के बीच-बीच में सोशल मीडिया पर झाँकते हैं, और रात गहराने पर भी युवाओं की आंखें नीली रोशनी में डूबी रहती हैं। हाल की एक रिपोर्ट ने साफ किया है कि स्क्रीन टाइम की लत ध्यान में कमी, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या, सामाजिक अलगाव और अवसाद जैसी परेशानियों को जन्म दे रही है। यह स्थिति धीरे-धीरे 'साइलेंट क्राइसिस' यानी मौन संकट का रूप ले चुकी है।

स्क्रीन की गिरफ्त में फँसे बच्चे न तो अपने माता-पिता से खुलकर बातें करते हैं और न ही पड़ोस-मित्रों के साथ खेलकूद में रुचि लेते हैं। परिवार की बातचीत 'ऑनलाइन चैट' से हार जाती है और रिश्तों की गर्माहट 'इमोजी' तक सिमट जाती है। यह लत युवाओं को वास्तविक जीवन से दूर ले जाकर एक कृत्रिम दुनिया में कैद कर रही है।

कक्षा में बच्चों का ध्यान भटकना, किताबें पढ़ने का उत्साह कम होना, परीक्षा में अंक गिरना-ये सब स्क्रीन एडिक्शन के दुष्परिणाम हैं। लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने से आंखों की रोशनी पर असर, सिरदर्द, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता जैसी समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। सबसे खतरनाक असर यह है कि युवा अपनी पहचान और आत्मविश्वास को 'लाइक्स' और 'फॉलोअर्स' पर टिका देते हैं। वे आभासी दुनिया की तालियों और इमोजी पर अपने असली जीवन का मूल्यांकन करने लगते हैं, जिससे आत्मसम्मान कमजोर होता है।

इस समस्या का हल परिवार और समाज मिलकर ही निकाल सकते हैं। माता-पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम पर सीमाएँ तय करनी होंगी। खाने की मेज पर, पढ़ाई के समय और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल न करने का नियम परिवार से ही शुरू होना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना होगा ताकि वे आभासी सहारों की बजाय असली रिश्तों की गर्माहट में जीना सीखें।

स्कूल-कॉलेजों में भी डिजिटल अनुशासन की ज़रूरत है। 'डिजिटल डिटॉक्स डे', 'नो मोबाइल ज़ोन' जैसी पहलें बच्चों को राहत दे सकती हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे पढ़ाई के अलावा खेल, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में युवाओं को शामिल करें। इससे बच्चों को स्क्रीन से परे वास्तविक जीवन की खूबसूरती का अहसास होगा।

समाज को भी इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा। नशामुक्ति और स्वच्छता अभियानों की तरह 'संतुलित स्क्रीन उपयोग' पर भी सामूहिक पहल की जा सकती है। पार्कों, पुस्तकालयों और सामुदायिक केन्द्रों को इस तरह सक्रिय करना होगा कि युवाओं को विकल्प मिल सकें। खेलकूद, संगीत, पठन-पाठन और सामूहिक गतिविधियाँ बच्चों को स्क्रीन से दूर करने के बेहतर साधन हो सकते हैं।

स्क्रीन एडिक्शन केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौती है। यदि हम इसे अभी गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होकर खड़ी होंगी। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों और युवाओं को तकनीक का दास नहीं, बल्कि उसका सशक्त उपयोगकर्ता बनाना सीखाएँ। यही भविष्य की स्वस्थ और सशक्त समाज रचना का मार्ग है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

भिया का एटम बम...!

व्यंग्य

भूपेन्द्र भारतीय
लेखक व्यंग्यकार हैं।

भिया ने एक बम बनाया है। ओर ना सिर्फ बम बनाया है पर एटम बम बनाया है। यह सब बहुत गोपनीय तरीके से किया गया है। यह एटम बम कोई ऐसा-वैसा बम नहीं है। यह किसी सेना का हथियार या फिर सामरिक शक्ति नहीं है। यह तो भिया की साहित्यिक शक्ति का परिचय होगा। बौद्धिक शौर्य का प्रतीक बनेगा। दुनिया थरथरा जाऐगी। विश्व साहित्य बिरादरी में नई चर्चा शुरू होने वाली है। क्योंकि भिया ने साहित्य में एटम बम बनाया है। हाँ चौंकिए मत। साहित्य में भी एटम बम बन सकता है। साहित्य जगह में इस बम से तहलका मचने वाला है। इस बम के माध्यम से भिया साहित्य के मंचों पर अपनी शक्ति का परिचय देगें। बड़े बड़े मंच डगमग-डगमग डोलेगें। भिया अब तक राजनीति में बड़े बड़े बम ला चुके हैं लेकिन इस बार उनका मन हुआ कि क्यों नहीं साहित्य में भी एक ऐसा बम बनाया जाए। जिसमें बाकी सारे साहित्यकार धराशायी हो जाए। अब वे साहित्य के माध्यम से राजनीति का मार्गदर्शन करेंगे। राजनीति को साहित्य का सहारा देगें।

अब भिया ने साहित्य के क्षेत्र में बम बनाया है तो निस्संदेह यह फटेगा ही। ओर जोरदार ही फटेगा। इसकी गूंज आप हम सब सुनेंगे। ऐसा उन्हें अटल विश्वास है। कितने पाठक, साहित्यकार साहित्यिक संस्थाएं इस साहित्यिक एटम बम की निशाने पर आयेंगे यह देखना रोचक रहेगा। वैसे भिया का दावा है कि वे इस बम से साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े धमाके करने वाले है। इस बम से कितने ही साहित्यकारों की जमीन हिल जाऐगी। भिया का यह बम साहित्य में विरोधियों के लिए आफत तो साबित होगा ही, साथ ही साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। एकदम नये रसों व भावों के मिश्रण से भिया ने इस बम को बनाया है। हो सकता है विरोधियों को तो यह बम समझ में ही ना आये और आम पाठक के लिए यह मुश्किल रहेगी कि उन्हें इस बम की भाषा समझने में कठिनाई होगी। पहले भी भिया की भाषा को लेकर जनता में भारी दुविधा रही हैं। जैसे ही यह साहित्यिक बम फटेगा साहित्य में नयी लहर व हवाएं चलने लगेगी। इसके फटने से ना सिर्फ साहित्य अकादमियों की कुर्सियां बल्कि सत्ता की कुर्सियां तक हिल सकती हैं। भिया का यह एटम बम बारुद कम बवंडर से ज्यादा लबरेज होगा।'

इस साहित्यिक एटम बम में विदेशी बारूद का भी उपयोग किया गया है। हाँ इसबार माल तगड़ा ही लिया गया है। इसकी अधिकांश रचनाएं पाठकों के लिए नही आलोचकों के लिए रची गई है। इस एटम बम का उद्देश्य साहित्यिक रसास्वादन के लिए नहीं, अपितु साहित्यिक अकादमियों में मठाधीशों को चुनौती देने के लिए सृजन किया गया है। पाठकों को इस बम में रस मिलना मुश्किल है बल्कि उन्होंने ज्यादा रस लेकर पढ़ा तो वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकते है। इसलिए आम पाठक को भिया के इस साहित्यिक एटम बम से दूर ही रहना चाहिए। ओर आम पाठक को भिया की इस रचना को खरीद कर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ भिया किसी पाठक को भेंट करें तो सावधानी बरतकर पढ़ना होगा। साथ ही आम पाठक इस एटम बम के सभी संभावित खतरों से स्वयं की रक्षा करने का ध्यान रखें। सावधानी के लिए भिया ने यह सब एटम बम की भूमिका में पहले ही लिख दिया है। वे शपथपत्र के साथ पहले ही कह चुके है कि उन्हें इस बम से कोई मानव सेवा व कल्याण नहीं करना है। वे तो इसे सिर्फ़ साहित्यिक खेमों में बवंडर लाने के लिए लाये है।

इस एटम बम को लाने के पीछे भिया का मूल कारण विरोधियों को साहित्यिक बारुद चटाना है। विपक्ष में खलबली मचाना है। जनता भिया से भ्रमित रहे और उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं करें। इसलिए भिया ने अपने खालीमाली समय में इस अद्भुत बम का सृजन किया है। आप इसे भिया की स्वांतः सुखाय रचना भी मान सकते हैं। यह आपकी परेशानी है। इसमें भिया कोई भलाबुरा नहीं मानेंगे। यह सब भिया ने साहित्य प्रेम के वशीभूत होकर किया है। भिया इसके अलावा किसी के अधीन नहीं है और ना ही वे किससे से डरते है। उन्हें किसी की आलोचना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी धुन के पक्के है। इसलिए भिया के इस एटम बम से बचकर रहें। यह कब भी और कहीं भी फट सकता है। वैसे इस बम की मारक क्षमता व सत्यता पर भिया कोई प्रमाण नहीं देगें और ना ही देना चाहते है। भिया बाजार में एटम बम लाये! उनका काम पूरा हुआ। अब आप इससे निपटो।

'अरे कहना क्या चाहते हो-अच्युत पोतदार'

सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है- ये वाक्य सुनते ही फिल्म अभिनेता अजीत का चेहरा सामने आ जाता है । शोले के सांभा से जब हम 'पचास हजार' मात्र ये दो शब्द सुनते हैं तो मैकमोहन हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं । ऐसे ही सोशल मीडिया पर चलने वाली रील्स और मीम्स में 'थ्री इडियटस' फिल्म के एक दृश्य की क्लिप हिट हुई जिसमें प्रोफेसर, आमिर खान से मशीन की डेफिनेशन पूछते हैं, और आमिर तकनीकी दृष्टि से सही परिभाषा नहीं बता पाता है तो प्रोफेसर उसे क्लास से बाहर जाने के लिए कहते हैं ।

स्मृति शेष

सुनील सक्सेना

लेखक शिक्षक हैं।

कला का क्षेत्र बड़ा अप्रत्याशित है। अक्सर ये होता है कि किसी विधा में अपनी पूरी जिंदगी खपा देने के बाद भी, उत्कृष्ट काम करने के बावजूद व्यक्ति को वो पहचान नहीं मिल पाती है जिसका वो हकदार होता है। ऐसे में कई प्रतिभाएं गुमनामी के अंधेरे में हमेशा-हमेशा के लिए खो जाती हैं । लेकिन कभी-कभी कोई गायक किसी एक गाने से, कोई कवि किसी एक कविता से, कोई अभिनेता किसी एक संवाद से जनमानस में लोकप्रिय हो जाता है, लोगों के दिलों पर राज करने लगता है या कहें अमर हो जाता है।

'सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है' ये वाक्य सुनते ही फिल्म अभिनेता अजीत का चेहरा सामने आ जाता है। शोले के सांभा से जब हम 'पचास हजार' मात्र ये दो शब्द सुनते हैं तो मैकमोहन हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं।

ऐसे ही सोशल मीडिया पर चलने वाली रील्स और मीम्स में 'थ्री इडियटस' फिल्म के एक दृ?य की क्लिप हिट हुई जिसमें प्रोफेसर, आमिर खान से मशीन की डेफिनेशन पूछते हैं, और आमिर तकनीकी दृष्टि से सही परिभाषा नहीं बता पाता है तो प्रोफेसर उसे क्लास से बाहर जाने के लिए कहते हैं।

आमिर खान क्लास में वापस आते हैं किताबें लेने के लिए। प्रोफेसर के पूछने पर कि वे क्यों आए तो आमिर जिस अंदाज में 'किताब' का वर्णन करते हैं प्रोफेसर भोंचक्का रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो आमिर से कहता है - 'अरे कहना क्या चाहते हो'। इस मकबूल संवाद को पर्दे पर बोलने वाले प्रोफेसर की भूमिका में अच्युत पोतदार थे। उनके द्वारा बोला गया ये डायलॉग वायरल हो गया। इस संवाद से उन्हें जो पहचान, मकबूलियत मिली वो लगभग सौ से ऊपर फिल्में, दर्जनों धारावाहिक और हिंदी-मराठी नाटकों में काम करने के बावजूद उन्हें नसीब नहीं हुई ।

मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे अच्युत पोतदार का 19 अगस्त को 91 वर्ष की उम्र में मुबंई में निधन हो गया। अच्युत पोतदार ने सेना की नौकरी से निवृत्त होकर, भारत सरकार के उपक्रम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अधिकारी के पद पर वर्ष 1992 तक काम किया।

उनका अभिनय का शौक रंगमंच से होकर फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में उन्हें ले आया। अच्युत पोतदार ने गोविंद निहलानी की 'आक्रोश' फिल्म से अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था। अस्सी के दशक के समानांतर सिनेमा के दौर में उनका ऐसा जलवा-जलाल था कि लगभग हर आर्ट फिल्म में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में वे नजर आते थे।

कला फिल्मों के अलावा रंगीला, दामिनी, मुन्ना भाई एम बी बी एस, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी अच्युत पोतदार ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है।

'तेजाब' फिल्म में अच्युत पोतदार ने अनिल कपूर के पिता की भूमिका की थी। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। मुझे इंडियन ऑयल ज्वाइन किए लगभग दो वर्ष हो गए थे जब ये फिल्म रिलीज हुई। पता चला कि पोतदार जी तो हमारे इंडियन ऑयल में मैनेजर पीआर के पद पर हैं।

प्रसंगवश यहां ये उल्लेख करना चाहूंगा कि इंडियन ऑयल परिवार से कला जगत की कई मशहूर हस्तियां जुड़ी रही हैं। 'दाग ढूंढते रह जाओगे' सर्फ के विज्ञापन से रातों रात मशहूर हुई कलाकार आसावरी जोशी के पिता सतीश तुंगारे इंडियन ऑयल में थे। मशहूर फिल्म कलाकार अमरीश पुरी के भाई हरीश पुरी इंडियन ऑयल का हिस्सा रहे ।

तो मैं भोपाल में शौकिया रंगमंच पर सक्रिय था। कलाकार होने के नाते जाहिर है अच्युत पोतदार से मुलाकात करने के लिए मैं बेताब हो गया । वे मुंबई में पोस्टेड थे । 'तेजाब' देखने के अगले दिन ही तुरंत उन्हें मैंने पत्र लिखा । उनकी एक्टिंग की तारीफ से भरा और ये भी पूछा कि नौकरी के साथ अभिनय को आप कैसे साध लेते हैं ? उनका जवाब आया । मुझे मेरी रंगयात्रा की के लिए शुभकामनाएं दी। फिर उनसे ऐसा राब्ता हुआ कि मुंबई में मेरी चार साल की पोस्टिंग में कुछ एक मुलाकातों में उनसे अभिनय और फिल्मी इदारे के बारे में नजदीक से जानने-समझने को बहुत मिला।

अपने अभिनय कौशल से साधारण से चरित्र को विशेष बना देने की अद्भुत क्षमता अच्युत पोतदार जी के पास थी। फिल्म दर फिल्म चरित्र भूमिकाओं में नए मील के पत्थर वे गढ़ते रहे। बढ़ती उम्र के साथ जिस जोश, जज्बे और जुनून से अच्युत पोतदार फिल्मों, विज्ञापन में सक्रिय थे, वे युवा संघर्षरत कलाकारों के लिए एक अप्रतिम नज़ीर हैं।

सआदत हसन मंटो ने कहा है - मौत कुदरत की एक खामी और बदसूरत चीज़ है। सच है मृत्यु अकाट्य सत्य है। इसे कोई नहीं टाल सकता। अच्युत पोतदार का इस फानी दुनिया से कूच करना, मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पर बड़ी क्षति है ही, फिल्म बिरादरी ने भी अपना एक नेक और शानदार अभिनेता खो दिया है । विनम्र श्रद्धांजलि। अच्युत पोतदार जी आप बहुत याद आएंगे ।

ट्रम्पिया गए हो का...

वक्रोक्ति

सुरेश उपाध्याय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सेवानिवृत्त होने की उम्र साठ वर्ष थी। जैसे जैसे यह तिथी नजदीक आ रही थी मित्रों, परिचितो, रिश्तेदारों ने उन्हे सचेत करना शुरु कर दिया था, 'गुरु सठियाने के दिन गिनती के रह गए हैं'। गुरु ने तभी से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ठान ली थी। वह अपने आप को 'साठा सो पाठा' सिद्ध करने की जुगाड में लग गए थे। शारीरिक व मानसिक दोनो स्तर पर अपने आप को सिद्ध करने के लिए उन्होने प्लानिंग करने का मन बना लिया था। इस संदर्भ के लिए पुस्तको और गूगल को खंगालना उन्होने शुरु कर दिया थी। खानपान में बादाम, अखरोट, फल व फलों के रस आदि को जोड़ने तो कसरत में सुबह की सैर, साइकलिंग, प्राणायाम, जीम आदि की तैय्यारी कर ली थी।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए लायब्रेरी की सदस्यता, पठन-पाठन के साथ लेखन में हाथ आजमाने की भी तैय्यारी प्लानिंग का हिस्सा थे। अंततः वह दिन आ ही गया और प्लेटिनम जयंति पर हार-फूल, स्वागत-सत्कार, पार्टी-शार्टी में कब व कैसे दिन निकल गया पता ही नही चला। दूसरे दिन सुस्ताते हुए उठने में थोड़ा विलम्ब हुआ और सठियाने का लांछन जो पीछे लगा तो उनकी प्रत्येक कामकाज, गतिविधि पर प्रतिक्रिया का हिस्सा बन गया। खास से लेकर आम तक उनके सठियाने की याद दिलाने लगे। घर-परिवार तक में किसी विषय पर उनकी सलाह, सुझाव, हस्तक्षेप की प्रवृत्ति पर चुप करने का रामबाण इलाज 'सठियाने की घुडकी' बन गई। प्लानिंग (नियोजन) का एक्सीक्यूसन (क्रियांवयन) करने के उनके सारे जतन धरे रह गए। उन्हे धरम-करम के उपदेश दिए जाने लगे तो कर्मकांड पर 'सौ चूहे खाकर हज जाने' जैसे ताने सूनने को मिलने लगे, उनकी प्रगतिशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगे। स्थितिया कुछ ऐसी बनी की उन्होंने भी समझौता करना ही ठीक समझा और 'साठा सो पाठा' को तिलांजली देकर अपने आपको सठिया गया मानने में ही भलाई समझी। अचानक वैश्विक न्यू नार्मल ने उनका ध्यान आकृष्ट किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियो, कार्यक्रमों, गतिविधियों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। उन्होने पाया कि वे अचानक फैसले लेते हैं और अचानक यू टर्न भी ले लेते है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के उनके नारे ने अनेकों देशों को प्रेरित किया और वे सब अपने अपने नेशन को ग्रेट बनाने के नारे के साथ मैदान में उतर गए। यह नारा आकर्षक सिद्ध हुआ तथा कईयो को चुनावी वैतरणी पार कराने में सहायक सिद्ध हुआ। खुली धमकियों से दुनिया के समीकरण बदलने लगे, मित्रताएं टूटने लगी, नई मित्रताए बनने लगी। वह कभी युद्ध के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करते तथा सहयोग व हथियार उपलब्ध कराते तो कभी युद्ध विराम के लिए डांट लगाते तथा अपने आप को शांति का मसीहा घोषित करते 'नोबल शांति पुरस्कार' की आकांक्षा रखते। कुछ देशो ने उनके नाम के लिए अनुशंसाए भी इस पुरस्कार के लिए कर, उन्हे खुश करने की कोशिश की। जो उनके सुझाव, सलाह, परामर्श से सहमत नही होता लगता उनके लिए व्यापार प्रतिबंध, शर्त, टेरिफ व पेनल्टी को उन्होने टूल (औजार) बना लिया। जिन देशो की उन्होने मदद की उनसे उन्होने स्वाभाविक कुछ अपेक्षाए भी की। प्रवासियों का निष्कासन, धमकी, प्रलोभन, स्वार्थ को राष्ट्रवाद का न्यू नार्मल बनाकर उन्होने अपने राजकोष में इजाफा कर दुनिया को एक नई दिशा प्रदान की। हर अच्छे काम में अड़चन तो आती ही है, दुनिया में डंका बजाने के फेर में उनकी लंका में भी थोडी आग तो लगनी ही थी, कुछ विरोध हुआ, कुछ न्यायिक फैसलों ने निर्णय पलट, कुछ यू टर्न लेना पड़ा।

गुरु ने भी इन पैतरों का इस्तेमाल शुरु किया - घर में आर्थिक सहयोग कम कर दिया, अपने घूमने-फिरने/ऐशो-आराम में खर्च बढ़ा दिया। परिवार के सदस्यो, मित्रो, परिचितो में इधर-उधर करना, एक-दूसरे के खिलाफ भडकाना, झगड़ा बढ़ने पर सुलझाना व उसका श्रेय लेना तथा जरुरत पड़ने पर मदद न करना / मदद न करने की धमकी देना आदि का प्रभावी प्रयोग शुरु कर दिया। उनके व्यवहार से लोग चमकने लगे, अतिरिक्त सतर्कता बरतने लगे तथा सठियाने के ताने मारना भूल गए। गुरु की पत्नी तो उनकी रग रग से वाकिफ थी। गुरु ने जब इनका प्रयोग अपनी पत्नी पर किया तो इस बार उन्हे सठियाने की झिड़की नहीं मिली, मुस्कुराते हुए वह बोली ' ट्रम्पिया गए हो का'।

कर्तव्यपालन के साथ मानवीयता का पुलिसीय चेहरा

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

घटना कुछ ऐसी है कि देवास जिले के कन्नौद क्षेत्र में चोरी का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही 5 मिनट के भीतर थाना प्रभारी तहजीब काजी घटनास्थल पर पहुंचे। चोरों का पीछा किया, इस दौरान एक चोर भागते-भागते करंट की चपेट में आकर घायल हो गया। पुलिस वाहन लगभग 1 किलोमीटर दूर था। रास्ता उबड़-खाबड़ था। ऐसी स्थिति में पकड़े गए घायल चोर को थाना प्रभारी अपनी पीठ पर लाद कर 1 किलोमीटर दूर अपने वाहन तक पहुंचे। जाहिर है कि चोर बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी अब तक की गई चोरियों का स्वत-खुलासा कर दिया ।

इस घटना से समस्त पुलिस-प्रशासन के छोटे-बड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक सीख लेने की अत्यंत आवश्यकता है। निश्चित रूप से पुलिस ने अपने मूलभूत कर्तव्य को मूर्त रूप देते हुए मानवीय सरोकार का जीवंत परिचय दिया। इसके अतिरिक्त भागते चोर राजू के साथ मानवीय व्यवहार आजकल के दौर में प्रकारांतर से सामाजिक सौहार्द का पुलिसिया परिचय भी दे गया। इसमें दो मत नहीं कि आम नागरिकों के जनजीवन में जान माल की अहम सुरक्षा का भार पुलिस प्रशासन के कंधों पर ही होता है। निश्चित रूप से पुलिस अपराध की तहकीकात के दौरान बहुचर्चित थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल करती है। खैर।

इस कारण ऐसा समझा जाता है कि पुलिस वालों के दिल में 'दल ' नाम की चीज शायद ही होती है। आमतौर पर पुलिस एवं पुलिसिया गतिविधियों को लेकर आम नागरिकों के अंतर्मन में नकारात्मक भाव अधिक देखने में आया करता है। हालांकि पुलिस का वास्ता प्रतिष्ठित एवं संभ्रांत नागरिकों से कम ही पड़ता है। वैसे इसकी वजह बड़ी साफ है कि पुलिस प्रशासन का कार्यक्षेत्र ही ऐसा है कि छोटे-बड़े तमाम अपराधियों की गतिविधियों पर स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान अधिक रहा करता है। बहुत कम पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने पारिवारिक संस्कारों के चलते अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठित नागरिकों से जीवंत संपर्क रखा करते हो।

आम नागरिकों के एक प्रकार से हितचिंतक प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय तथा क्षेत्रीय मीडियाकर्मियों से पुलिस प्रशासन का जीवंत संपर्क होता है। जिसके चलते पुलिस-प्रशासन को अपने कर्तव्यपालन के प्रति अत्यधिक सचेत अवस्था में रहना पड़ता है। काफी हद तक पुलिस प्रशासन की निरंकुश कार्यशैली पर अंकुश लगाने में इन मीडिया कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा करता है। वैसे नगरीय एवं शहरी क्षेत्र में अलग-अलग त्योहार की पूर्व बेला में पुलिस प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंध में संबंधित क्षेत्र के संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ 'शांति समिति की बैठक' अवश्य ही आयोजित की जाती है।

जिसके चलते पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अन्य विभागों को भी इस बैठक में विभिन्न शिकायत एवं सुझावों से सामना करना होता है। शिकायतों का त्वरित निराकरण एवं प्राप्त सुझावों का गुण-दोष के आधार पर अमलीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। इस बैठक के अतिरिक्त संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित नागरिकों से प्रत्यक्ष संवाद की स्थिति आमतौर पर नहीं बना करती ।

यही एक कारण है कि आम जनमानस में पुलिस प्रशासन के प्रति जमाने भर की गलतफहमियां घर कर जाती है।

विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे की आमला नगर को सौगात, सवा दो करोड़ रुपए लागत के निर्माण कार्यों के टेंडर जारी

आमला सारणी विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के प्रयासों से मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना चतुर्थ चरण अंतर्गत अभी तक पौने पांच करोड़ रुपए लागत के निर्माण कार्यों की मिल चुकी है स्वीकृति

- **जारी टेंडर में बस स्टैंड से चंद्रभागा नदी तक सड़क पर डिवाइडर एवं आकर्षक केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था, सौंदरीकरण एवं मुख्य सड़क निर्माण समेत अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य होने है**
- **विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के रंग लाए प्रयास, आमला नगर को अधोसंरचना विकास की बड़ी सौगात**

बैतूल/आमला। आमला-सारणी विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के प्रयासों से आमला नगर के सर्वांगीण एकीकृत विकास एवं आमला शहर के सौंदरीकरण व मुख्य सड़क निर्माण समेत अन्य कार्यों के लिए आमला नगर को आज बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। नगर पालिका द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना (चौथा चरण) अंतर्गत स्वीकृत सवा दो करोड़ रुपए लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों हेतु निविदाएँ जारी की गई हैं। इन कार्यों में बस स्टैंड से चंद्रभागा नदी तक सड़क पर डिवाइडर एवं आकर्षक केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था जनपद चौक से तहसील कार्यालय वाली मुख्य सड़क तक सीसी रोड एवं दोनों ओर नालियों का निर्माण जनपद चौक का सौंदरीकरण कार्य, पुलिया निर्माण समेत अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य सम्मिलित है ।

गौरतलब है कि विधायक डॉ. पंडाग्रे के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के साथ साथ संस्थागत अधोसंरचना उन्नयन के लिए सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना (चतुर्थ चरण) अंतर्गत कुल पौने पांच करोड़ रुपए लागत के निर्माण कार्यों की सौगात मिल चुकी है जिनमें आमला जम्बड़ा रोड पर नगर पालिका परिषद आमला के लिए सर्वसुविधा युक्त भव्य निर्माणाधीन कार्यालय एवं हल ही में जारी टेंडर में स्वीकृत कार्य सम्मिलित है।

नगर के विकास को केंद्रित है दीर्घकालीन एकीकृत विकास कार्ययोजना- विधायक डॉ. पंडाग्रे के द्वारा आमला नगर को केंद्रित दीर्घकालीन एकीकृत विकास कार्य योजना के क्रियान्वयन की श्रृंखला में जल्द 1 करोड़ से अधिक लागत से कायाकल्प 2.0 योजना अंतर्गत नगर में विभिन्न रोड,नली निर्माण एवं एसबीएम 2.0 अंतर्गत एमआरएफ सेट निर्माण समेत अन्य कार्यों का भूमिपूजन जल्द किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 8 करोड़ रुपए से अधिक लागत लागत से उपयोगित जल प्रबंधन सम्बंधित निविदा प्रकिया निर्णायक प्रगति पर है। हाल ही में भोपाल प्रवास के दौरान विधायक डॉ. पंडाग्रे ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विभागीय मंत्री एवं अधिकारियों से भेंट कर विशेष निधि से नगर में रोड, नालियों एवं अन्य अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु विशेष अनुदान स्वीकृति का आग्रह किया है। जिनकी स्वीकृति शीघ्र मिलने की संभावना है।

विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे ने चर्चा के दौरान कहा कि जल्द क्षेत्र को अनेकों और सौगातें मिलने जा रही है ।

आमला के नागरिकों ने जताया विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे का आभार- आमला नगरीय क्षेत्र के नागरिकों प्रबुद्ध जनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों नगर में करोड़ों रुपए लागत वाले निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं आमला नगर के हित में ऐतिहासिक सौगात दिलाने हेतु क्षेत्रीय विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया है।

इनका कहना है

मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत करोड़ों रुपए के निर्माण स्वीकृति एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आमला नगर की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हु।

- डॉ. योगेश पंडाग्रे,
विधायक आमला सारणी
विधानसभा

नगरपालिका कचरे से खाद बनाकर बढ़ा सकती है आय, लेकिन अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

ट्रेंचिंग ग्राउंड में निकली खाद को नपा बांट रही निःशुल्क

संजय द्विवेदी, बैतूल। नगरपालिका ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे की प्रोसेसिंग करवा रही है। इसका बकायदा ठेका भी दिया गया है। प्रोसेसिंग के दौरान जो खाद निकल रही है, उसे खराब बताकर नगरपालिका निशुल्क बंटवा रही है। जानकार कहते है कि अगर नगरपालिका इस खाद को बेचती है तो यह नपा की आय का जरिया बन सकती है। दरअसल शहर के 33 वार्डो से करीब 35 टन कचरा निकलता है। यह कचरा गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में वर्षो से जमा हो रहा है। जिससे यहां कचरे का ढेर लग गया है। इस कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन के लिए वर्तमान में लेगेसी वेस्ट प्लांट का संचालन किया जा रहा हैं। इस दौरान कचरे से बड़ी मात्रा में खाद भी निकल रही है। लेकिन नगरपालिका इसे निशुल्क बंटवा रही है। जानकार बताते है कि प्रोसेसिंग के जरिए केमिकल डालकर आसानी से अच्छी क्वालिटी का खाद इसी कचरे से बनाया जा सकता है। लेकिन नपा अधिकारी इस कार्य में दिलचस्पी नहीं ले रहे है। यहां तक कि खाद की अच्छी क्वालिटी नहीं होने की बात कह रहे हैं।

कचरे में निकल सकती है 20 प्रतिशत खाद - ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 86 हजार टन कचरा नष्ट करने पर 20 प्रतिशत यानी 17 हजार टन खाद आसानी से बन सकती थी। वहीं कचरे से निकल रहे रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल का भी नपा उपयोग नहीं कर रही है। नपा के पास पहले ही राजस्व की कमी है, बजट के खजाने खाली हैं यदि इस खाद को बाजार में प्रोसेसिंग करके बेचा जाता तो आसानी से लाखों रूपये की आमदनी हो सकती थी। जानकार बताते है कि आमतौर पर वर्षो तक जमीन में कचरा दबे रहने से 20 प्रतिशत खाद बन जाती है। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारी कहते है कि कचरे से बनने वाली खाद का उपयोग खेतों में किया जा सकता है, बशर्त है कि खाद की पहले जांच कराई जाये, क्योंकि कचरे में कई हानिकारक एलीमेंट होते है। ऐसे में इस खाद का सीधे खेतों में इस्तेमाल किये जाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति प्रभावित हो सकती है और इसका दुष्परिणाम भी सामने आ सकते है।

रोजाना निकलने वाले कचरे का लग रहा ढेर- ट्रेंचिंग ग्राउंड में, जो प्लांट वर्तमान में संचालित हो रहा है उसके टेंडर केवल 1.35 लाख टन पुराने कचरे के निष्पादन के लिए किए गए हैं। जिसमें से 86 हजार टन कचरा खोदकर बाहर निकाला जा चुका है। इसमें 20 प्रतिशत यानी 17 हजार टन खाद आसानी से बन सकती थी। हालांकि अभी भी ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे के 20 से 25 फीट ऊंचे पहाड़ लगे हुए हैं। खोदकर निकाला कचरा भीगने और कीचड़ होने से बदबू और मक्खियों का अंबार लग रहा है। जिससे आसपास के लोग परेशान हैं, इन्हे अभी लंबे समय परेशान होना पड़ सकता है। यदि पूरी तरह प्रोसेस किया जाए, तो खाद बिक सकती है।

200 रुपये में मिलता है 50 किलो का बैग

जानकार बताते है कि बाजार में खाद का 50 किलो का बैग करीब 200 रुपये में बिकता है। यदि नगरपालिका कचरे से निकलने वाली खाद का विक्रय करे तो नगरपालिका को अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। लेकिन नगरपालिका इस खाद का निशुल्क वितरण कर रही है। कुछ जानकारों का मानना है कि जो खाद कचरे से निकल रही है, उसकी थोड़ी बहुत प्रक्रिया के बाद उसे पूरी तरह खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। जिससे नगरपालिका बेच कर अपनी आय बढ़ा सकती है। लेकिन नपा इसमें तत्व नहीं होने का हवाला दे निशुल्क बांट रही है। जबकि प्रोसेसिंग के जरिए केमिकल डालकर आसानी से अच्छी क्वालिटी का खाद इसी कचरे से बनाया जा सकता है।

इनका कहना है -

अभी मुझे ट्रेंचिंग ग्राउंड की फाइल नहीं मिली है। फाइल मिलने के बाद देखकर ही इस संबंध में कुछ पता पाऊंगा।

- पंकज धुर्वे, सब इंजीनियर,
नगरपालिका बैतूल

ट्रेंचिंग ग्राउंड से जो कचरा निकल रहा है, उस कचरे को खाद में बदलने के लिए विभिन्न एजेंसियों से बात कर प्लानिंग की जा रही है। जिससे नगर पालिका को आय प्राप्त हो सके।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ,
नगरपालिका बैतूल

संपूर्णता अभियान में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को स्वर्ण पदक

प्रदेश स्तर पर धार जिले के तिरला ब्लॉक की उत्कृष्ट उपलब्धि

धार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को संपूर्णता अभियान के तहत तिरला आकांक्षी ब्लॉक में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। यह सम्मान राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किया गया। नीति आयोग और राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 में शुरू किया गया संपूर्णता अभियान आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास की गति तेज़ करने की एक विशेष पहल है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और सामाजिक विकास से जुड़े छह-छह प्रमुख संकेतकों को सौ प्रतिशत तक पहुँचाना है। इनमें गर्भवती महिलाओं की जाँच व पोषण, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, स्कूलों में बिजली और किताबों की उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग जैसे कार्य शामिल हैं।

सद्भावना, भाईचारे और प्रगतिशील सोच के प्रेरणा पुंज थे राजीव गांधी: निलय डागा

जिले में कांग्रेसजनों ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी की जयंती

बैतूल। पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी की जयंती को पूरे जिले में कांग्रेसजनों ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभाएं हुईं। जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष निलय डागा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने अपने-अपने क्षेत्र में रक्तदान भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

नव नियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी सूचना क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश को आधुनिकता और तकनीकी विकास की ओर अग्रसर किया। आज हम जिस कंप्यूटर और सूचना तकनीक के युग में जी रहे हैं, उसकी नींव राजीव गांधी जी ने ही रखी थी। उनका सपना था कि भारत विश्व के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो। उन्होंने युवाओं को राजनीति और विकास की मुख्यधारा में जोड़ा। उनका जीवन सद्भावना, एकता और प्रगतिशील विचारों का प्रतीक रहा। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांव-गांव तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में सदैव इतिहास में अमर रहेंगे। श्री डागा ने कहा कि राजीव गांधी जी की सोच सदैव प्रगतिशील और भविष्य की ओर देखने वाली रही। उन्होंने सद्भावना और भाईचारे को अपनी राजनीति का आधार बनाया। आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं, तब हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखने के साथ-साथ तकनीकी और शैक्षणिक प्रगति की दिशा में भी आगे बढ़ें। जिले के सभी ब्लॉकों में आयोजित इन कार्यक्रमों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। राजीव गांधी जी के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। सद्भावना, भाईचारे और सेवा की भावना से भरे इस आयोजन ने पूरे जिले को एकजुट कर दिया।

बेअरलॉकर ने ग्राम छोटा टिगरिया में की सौगातों की बौछार

देवास। जिला कलेक्टर श्री ऋषिराज सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री ज्योति शर्मा द्वारा जिले के स्कूलों को फर्नीचर व कम्प्युटर सुविधा युक्त किए जाने तथा ग्राम पंचायतो में भी आवश्यक सुविधाएँ जुटाने के अभियान में भागीदारी करते हुए आज बेअरलॉकर उद्योग ने अपने सामाजिक सरोकार के तहत क्षिप्रा संकुल के ग्राम छोटा टिगरिया के प्राथमिक शाला में 15 सेट फ़र्नीचर,माध्यमिक शाला में 40 सेट फ़र्नीचर,दो कम्प्युटर,150 लीटर क्षमता का एक आरओ, वाटर कूलर,तथा ग्राम में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण मरीज़ों की सुविधा हेतु एक व्हीलचेयर, पाँच सिटिंग बेंच,तथा 150 लीटर क्षमता का एक आरओ, वाटर कूलर भेंट किए,साथ ही सभी 75 बच्चों को बैग,12-12कापियां भी भेंट की ।

बेअरलॉकर उद्योग के सीएसआर प्रबंधक प्रवीण शर्मा तथा प्रोजेक्ट समन्वयक 'एक्ट ईव फाउंडेशन' अध्यक्ष मोहन वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत सीईओ सुश्री ज्योति शर्मा थी, अन्य अतिथियों में जनपद सीईओ श्रीमती हेमलता मंडलोई,स्वच्छ भारत मिशन समन्वयक श्री नागर, ग्राम सरपंच श्रीमती सुनीता विष्णु पटेल,संकुलप्राचार्य राजीव सूर्यवंशी,बीआरसी किशोर वर्मा बेअरलॉकर उद्योग के अमित नागजी, उपस्थित थे जिनका स्वागत स्कूल प्राचार्य शिवनारायन खेरिया ने किया । इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री ज्योति शर्मा ने बेअरलॉकर उद्योग का आभार मानते हुए उनके द्वारा समाज हित में किये जा रहे सहयोग की प्रशंसा की ।

कार की स्टेपनी बदलते समय ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत

बैतूल। बैतूल-इंदौर हाईवे पर मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में छिंदवाड़ा जिले के छापा खाना निवासी शेख फारूक (30) की मौत हो गई। हादसे में उनके भाई शानू घायल हो गए। घटना खेड़ी-सांवलीगढ़ के पास हुई। जानकारी के अनुसार, शेख फारूक अपने परिवार के साथ उज्जैन जा रहे थे। उनकी स्विफ्ट डिजायर कार हाईवे पर पंचर हो गई। स्टेपनी बदलते समय तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में फारूक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके भाई शानू को मामूली चोट आई। हादसे के बाद घायल परिवार को जिला अस्पताल बैतूल लाया गया।

प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, देवास में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हेतु भव्य दीक्षारंभ समारोह संपन्न

देवास। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, देवास में 20 अगस्त 2025 को पद्मश्री डॉ. नेमनाथ जैन ऑडिटोरियम, में प्रातः नए शिक्षण सत्र 2025-26 के शुभारंभ पर एक भव्य दीक्षारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान में प्रवेश लेने वाले एमबीए, एमसीए, बीबीए एवं बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया। यह संस्थान का 24वाँ बैच है। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्थान की छात्रा द्वारा गणेश वंदना की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी गई। जिसके बाद सरस्वती पूजन के साथ इस समारोह का शुभारंभ किया गया और देश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए राष्ट्रगीत गाया गया। कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. आर. के. जैन ने प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को दीक्षारंभ के बारे ने बताते हुए कहा कि यह एक मंगलाचरण है। इस संस्थान का चयन करने पर आप सभी छात्र- छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। हम आपको यहाँ एक विनम्र कॉर्पोरेट और विनम्र समाज का हिस्सा बनाते हैं, ताकि भविष्य में आप एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर विद्यार्थियों को रक्षा सूत्र बाँधकर संस्थान एवं अध्ययन के प्रति जिम्मेदार रहने की शपथ भी दिलाई गई। नवाचार का विशेष रूप से समायोजन करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. अनिल वाजपेयी ग्रुप डायरेक्टर, पीआईएमआर भोपाल ने यह कहा कि हमें विचारों की गुलामी को त्यागना होगा और सही रूप से स्वतंत्रता को अपनाते हुए, शिक्षा को वर्तमान परिवेश में सापेक्ष धरातल पर अंकित करना होगा। उन्होंने कृष्ण और सुदामा की कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि हमें अपने बारे में सोचने से पहले अपने देश, परिवार और संस्थान के बारे में सोचना चाहिए, तभी हम सच्ची प्रगति कर सकते हैं। दूर-दूर से आए हुए विद्यार्थी उनके संदेश को सुनकर अभिभूत हुए। कार्यक्रम के विशेष अतिथि कर्नल डॉ. वीरेन्द्र मिश्रा, फाउंडर डायरेक्टर, एकेडमी फॉर प्रोफेशनल एम्पावरमेंट एंड एक्सीलेंस, अमर सिंह बघेल, वाइस प्रेसिडेंट, वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, देवास ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में कौशल सीखना अत्यंत आवश्यक है। हमें स्वयं को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के अनुरूप विकसित करना होगा, ताकि आने वाले समय में हमारे पास रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। डॉ. राजीव रघुवंशी डायरेक्टर एडमिशन, प्रेस्टीज ग्रुप ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस पड़ाव के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिशा और दशा स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि सफलता सदैव सही दिशा के चयन से ही मिलती है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो गुण अत्यंत आवश्यक हैं दृ सकारात्मक दृष्टिकोण और सुसंस्कार एवं शिष्टाचार जो किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व और भविष्य की सफलता की आधारशिला बनते हैं। कार्यक्रम में डॉ. डेविश जैन प्रेसिडेंट, प्रेस्टीज ग्रुप ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा नए प्रवेशित छात्रों को आशीर्वाद दिया।

बिजली के खंभे पर झुलसा लाइनमैन

बैतूल। मुलताई के हिवरखेड़ गांव में बिजली का काम करते समय एक लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। दोपहर करीब ढाई बजे हुए इस हादसे के बाद उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुलताई ले जाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर उसे बैतूल ज़िला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हिवरखेड ग्राम आष्ठा के 28 वर्षीय लोकेश उत्तमराव कुनबी, बिजली के पोल पर चढ़कर जम्फर बदलने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक करंट लौटकर आने से वह बुरी तरह झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद उनके सहकर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर लोकेश को नीचे उतारा। उन्हें तुरंत मुलताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बैतूल रेफर कर दिया। ग्रामीणों ने इस हादसे को लेकर बिजली विभाग से सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए विभाग को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। लोगों ने विभाग से यह भी मांग की है कि घायल लाइनमैन को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोकेश अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और मेहनती हैं। इस घटना के बाद उनके परिजनों और साथी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

खाद्य विभाग ने सुपारी कारोबारकर्ता के गोदाम का किया औचक निरीक्षण

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच एवं नमूने लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन शैलेंद्र बड़ोनिया के मार्गदर्शन में 19 अगस्त को खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप पाटिल, पुरुषोत्तम भंडारिया, शशि भारतीय एवं पुलिस विभाग से एएसआई यादव द्वारा पाथाखेड़ा में बिना अनुज्ञप्ति के संचालित हो रहे एक सुपारी कारोबार कर्ता का औचक निरीक्षण किया गया। फर्म को वेद अनुज्ञप्ति प्राप्त करने तक बंद रखने के निर्देश दिए गए। फर्म से सुपारी के दो नमूने लिए गए। एजेंसियों से अचार

मसाला, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर के एक-एक नमूने लिए गए। लिए गए कुल 6 सैंपल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबार कर्ताओं को प्रतिष्ठान में साफ-सफाई रखने की हिदायत भी दी गई। यह कारवाई सतत जारी रहेगी।

कार्यालय नगरपालिका परिषद आमला
जिला-बैतूल (म.प्र.)

E-mail ID: cmoamla@mpurban.gov.in Office Ph.No-07147-285752

क्रमांक / लो.नि.शा./ ई–निविदा/2025/937 आमला, दिनांक–18/08/2025

// ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in/** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एव लागत	निविदा प्रपत्र कामूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2025_UAD _445036 Dt: 18-08-2025	Construction of various work in different wards, R.C.C.drain, C.C.Road and Janpad square beautification, divider/ street lighting, CMO house, HPC pipe culvertconstruction work, under CM Infrastructure Development Scheme (IV Phase). at ULB AMLA.	1-12 month 2- Rs. 2,23,71,507/-	1- Rs. 15,000/- 2- Rs. 1,12,000/-	Dt: 20-09-2025 Time: 17:30 pm

नोट :–निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन **https://mptenders.gov.in/** की वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा। उक्त निविदा सूचना निकाय की वेबसाईट **http://npamla.com/** पर भी देखी जा सकती है।

(श्री नितिन गाडरे) अध्यक्ष नगरपालिका परिषद आमला

(श्री किशोर माथनकर) उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद आमला

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद आमला

गंभीर परिस्थितियों में मरीज की जान बचाने के लिए करें एयर एंबुलेंस का उपयोग : कलेक्टर

पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत मिट्टी की मूर्तियों के उपयोग को दिया जाए बढ़ावा : कलेक्टर, पानी लेने के लिए टिल्लू पंप का उपयोग करने वालों के पंप किए जाएं जब्त: कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के समय-सीमा प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि आने वाले गणोशोत्सव एवं नवरात्रि के दौरान पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया जाए कि मूर्तियों का निर्माण पीओपी से नही हो बल्कि मिट्टी से हो। ताकि पीओपी से बनीं मूर्तियों के विसर्जन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय मूर्तिकारों को मिट्टी की मूर्ति बनाने और नागरिकों को मिट्टी की मूर्तियां खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि सीहोर में 14 जनवरी 1858 को आजादी के लिए प्राण न्योछावर करने वाले 358 अमर शहीदों की स्मृति में बनाए गए स्मारक एवं शहीद स्थल परिसर के संचालन और रखरखाव के लिए नगर पालिका सीएमओ तथा जनपद सीईओ बैठक कर कार्ययोजना बनाएं।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गंभीर परिस्थितियों में मरीज की जान बचाने के लिए निशुल्क एयर एंबुलेंस योजना चलाई जा रही है। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों के निर्मित होने पर मरीज की जान बचाने के लिए एयर एंबुलेंस की आवश्यकता हो तो उसका उपयोग किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को राहवीर योजना के तहत 25 हजार रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में होने वाले ज्ञात तथा अज्ञात वाहनों की दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को राहत राशि प्रदान करने की करवाई शीघ्रता से की जाए। इसके साथ ही घायलों को केंद्र सरकार की कैशलेश उपचार योजना का भी लाभ दिलाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि संबंल योजना के लंबित भुगतान के प्रकरणों में शीघ्र भुगतान की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही संबंल योजना के हितग्राहियों की परिवार आईडी को अपडेट किया जाए ताकि भुगतान में विलंब न हो। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने ग्रामीण उपभोक्ताओं तक प्रेशर के साथ पानी पहुंचने में हो रही समस्या की जानकारी मिलने पर कहा कि टिल्लू पंप उपयोग करने से ग्राम के आखिरी उपभोक्ता तक पानी का दबाव कम हो जाता है, इससे कई उपभोक्ताओं तक पर्याप्त मात्रा में पेयजल नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि टिल्लू पंप का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के टिल्लू पंप जब्त करने की कार्रवाई की जाए। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि नेशनल हाईवे, रेल परियोजनाओं, सिंचाई सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू अर्जन, मुआवजा वितरण, अर्जित भूमि का नामांतरण एवं कब्जा दिलाने के कार्य में प्रगति लाई जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय निकायों में पीएम आवास निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकन की कार्रवाई जल्द की जाए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि जिले में जहां 5000 से अधिक गायों के आश्रय के लिए बड़ी गौशालाएं बनाई जाना हैं, उनके लिए संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार गौशालाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराएं। उन्होंने वन खंडों के व्यवस्थापन एवं वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की अब तक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व एवं वन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन व्यवस्थापन एवं संपरिवर्तन की कार्यवाही में गति लाई जाए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि शासन के नियमों के अनुरूप सभी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी समय समय पर बैठक और समन्वय कर वन व्यवस्थापन और संपरिवर्तन के गतिरोध को दूर करें। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित पेंशन प्रकरणो एवं आगामी माहों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सेवानिवृत होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के सभी स्वत्वों एवं पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के साथ ही हो। उन्होंने निर्देश दिए कि शासकीय कर्मचारियों के सेवा अभिलेख सेवानिवृत्ति से पहले ही पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित पेंशन प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण कर जिला पेंशन कार्यालय को भेजें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन, अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, एसडीएम श्री नितिन टाले, श्री तन्मय वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती स्वाति मिश्रा, श्री सुधीर कुशवाह सहित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

अग्निवीर सेना भर्ती के लिए चिकित्सीय प्रबंध सुनिश्चित करें

विदिशा (निप्र)। अग्निवीर सेना भर्ती हेतु जिला चिकित्सालय में आकस्मिक चिकित्सीय प्रबंध और रिजर्व में 04 बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करनें हेतु निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर सेना भर्ती कार्यक्रम 20 अगस्त 2025 से 02 सितंबर 2025 तक जिला खेल परिसर स्टेडियम विदिशा में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें 15 जिलों से लगभग 500 से 600 आवेदक प्रतिदिन संख्या में भाग लेंगे। इस हेतु आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था हेतु जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में 04 बेड रिजर्व रख कर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिव महापुराण कथा महोत्सव में शामिल हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा

सीहोर (निप्र)। राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा इछावर तहसील के ग्राम बमुलिया में आयोजित श्री गोपेश्वर शिव महापुराण कथा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म हमे सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि धर्म के मार्ग पर चलकर मानव सेवा और दीन दुखियों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि जीवन में व्यक्ति को हमेशा बगैर किसी लालच और बिना किसी ईर्ष्या के अपने कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए। इस अवसर पर पंडित मोहितराम पाठक, श्री पंकज गुप्ता, श्री सुरेंद्र मेवाड़ा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

भगवान श्री रामलला के दर्शन का पहली बार मिला मौका, यात्रा संपन्न होने पर दिया धन्यवाद

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के कुरवाई निवासी श्री बाबूलाल पंथी, और उनकी पत्नी श्रीमती कला बाई को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत इस बार काशी बनारस अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहली बार मौका मिला था। उन्होंने बताया कि बहुत दिनों से भगवान श्री रामलला के दर्शन को जाने की सोच रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में नाम आने से हमारा यह सपना पूरा हो सका है। दोनों पति-पत्नी ने बताया कि तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी रही। खाना, पीना, रहना व दर्शन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए तीर्थ यात्री श्री बाबूलाल पंथी ने कहा कि प्रदेश के वयोवृद्ध नागरिकों को तीर्थ दर्शन कराने की यह योजना बहुत ही अच्छी पहल है। इस योजना से गरीब वयोवृद्ध नागरिक तीर्थ दर्शन कर पा रहे हैं वह भी बिना किसी व्यय खर्च के। सभी सुख-सुविधा इस योजना तहत प्रदाय की जा रही हैं। बिना किसी परेशानी के उनकी तीर्थ यात्रा संपन्न हुई इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त किया है।

नेशनल लोक अदालत 13 सितम्बर को

विदिशा (निप्र)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा श्री जाकिर हुसैन के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय के सभागार कक्ष में आगामी नेशनल लोक अदालत 13 सितम्बर 2025 के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक का आयोजन नोडल अधिकारी विशेष न्यायाधीश श्री जीसी शर्मा की अध्यक्षता में किया गया जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नीतेन्द्र सिंह तोमर एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत किया गया 381 बच्चों का टीकाकरण

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। जिले में 18 अगस्त को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 306 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 75 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही 35 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाईन और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन, विभागीय गतिविधियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभागवार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों और उनके निराकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाईन आमजन की समस्याओं, शिकायतों का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। अधिकारी शिकायत प्राप्त होते ही नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही प्रारंभ करें। संबंधित शिकायतकर्ता से चर्चा कर उन्हें भी निराकरण की प्रगति से अवगत कराएं। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जनपदवार पंचायत गैरतगंज, सांची, बेगमगंज, उदयपुरा, औबेदुल्लागंज सहित सभी जनपदों की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों और निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जनपद सीईओ गैरतगंज, सांची, औबेदुल्लागंज तथा अन्य जनपद सीईओ को सीएम हेल्पलाईन शिकायतें अधिक संख्या में लंबित होने पर एक सप्ताह में अंतिम निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार नगरीय निकायवार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों तथा निराकरण की प्रगति की समीक्षा कर सभी सीएमओ को निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमओ सांची को अनुपस्थित रहने तथा सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण को गंभीरता से नहीं लेने पर नोटिस जारी करने के निर्देश पीओ डूडा को दिए। इसी प्रकार बेगमगंज सीएमओ को भी पीएम आवास योजना शहरी में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन द्वारा केवल 38 प्रतिशत सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का ही निराकरण किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कार्य को गंभीरता से लेते हुए सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सीएमएचओ को भी प्राथमिकता से सीएम हेल्पलाईन निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री सीपी सोनी को छात्रावासों का सतत् भ्रमण नहीं करने तथा लापरवाह अधीक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने नॉन अटेन्डेन्ट सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की जानकारी लेते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, नगरीय प्रशासन तथा स्कूल शिक्षा विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों में जबाव दर्ज नहीं करने तथा अगले लेवल पर जम्प होने पर संबंधित अधिकारियों पर भी घोर नाराजगी व्यक्त की।

सांदीपनि विद्यालय में स्वच्छता का पाठः सीएमओ ने छात्रों को सिखाया ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

बैतूल (निप्र)। सांदीपनि शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को नगर परिषद बैतूल बाजार सीएमओ श्री विजय तिवारी ने छात्रों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कचरे को सही तरीके से अलग करने और उसके निपटान के महत्व पर जोर दिया, ताकि शहर और अपने विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। सीएमओ ने बताया कि कचरा, जिसमें प्लास्टिक, कागज, धातु, और फलों-सब्जियों के छिलके जैसी वस्तुएं शामिल हैं, हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित न किया जाए। उन्होंने नगर परिषद द्वारा अपनाई गई प्रणाली के बारे में बताते हुए छात्रों को समझाया कि कचरा गाड़ी में कचरे को दो अलग-अलग हिस्सों में लिया जाता है। श्री तिवारी ने विद्यार्थियों से एक पेड़ मां के नाम, घर का कचरा, कचरा वाहन में डालने और नलों में टोटी लगाकर जल संरक्षण की अपील की।

"कानूनी जागरूकता बच्चों के बहुमुखी विकास हेतु आवश्यक"

हरदा (निप्र)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति शर्मा के निर्देशन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रशेखर राठौर के मार्गदर्शन में सोमवार को तक्षशिला एकेडमी, द फाउंडेशन ऑफ ऐज्युकेशन तथा माँ शारदा विद्या मंदिर स्कूल हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने बच्चों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। वहीं, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व हैं। इसके साथ ही बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के तहत पॉक्सो एक्ट, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना की जानकारी उपस्थितजनों को दी गई। उन्होंने बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है।

जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में संचालित सभी योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जाए : सीईओ श्री जैन

बैतूल (निप्र)। जिला पंचायत सीईओ श्री अक्षत जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा की बैठक में हितग्राही मूलक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में संचालित सभी योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचना अनिवार्य है। योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित हों। सीईओ जैन ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के पट्टों को अपडेट कर नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण करें। साथ ही एफआरए पट्टा धारक को पीएमएफएमई, केसीसीसी, पीएम गरीब कल्याण योजना, वन अधिकार अधिनियम, धरती आबा योजना सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी जनपद सीईओ को धरती आबा योजना में वंचित गांवों की बस्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आईएफएमएस पोर्टल पर समग्र लिंकिंग कराए जाने के भी निर्देश दिए।

जिला स्तरीय ट्रेनर्स को ब्लॉक मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश : आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा के दौरान सीईओ श्री जैन ने राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त कर आए जिले के मास्टर्स ट्रेनरों से ट्रेनिंग संबंधी जानकारी ली। उन्होंने सभी जिला स्तरीय ट्रेनर्स को ब्लॉक के मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में 15 अगस्त को आयोजित ग्राम सभाओं में चयनित किए गए आदि सहयोगी और आदि साथी के नाम, नंबरों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर समस्याओं के निराकरण के लिए आदि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए शासकीय तथा पंचायत के भवन चिन्हित किया जाए और यहां साप्ताहिक एक घंटे की जनसुनवाई का सिस्टम भी लागू किया जाए। इसके अलावा उन्होंने क्लस्टर वार गांवों की जानकारी एसी ट्राईबल को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिए।

हितग्राहीमूलक आवेदनोयुक्त शिकायतो का फोर्सक्लोज ना करें

विदिशा (निप्र)। अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने सोमवार को लंबित आवेदनो की समीक्षा बैठक में हितग्राहीमूलक योजनाओं को क्रियान्वित कराने वाले विभागो के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इस प्रकार के आवेदनो का निराकरण शीघ्रतिशीघ्र कराएं। उन्होंने हितग्राहीमूलक आवेदनो का किसी भी प्रकार से फोर्सक्लोज कराने की प्रक्रिया क्रियान्वित नहीं की जाए। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित लंबित आवेदनो की समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर श्री डामोर ने विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन आवेदनो का निराकरण हो जाता है निराकरण की जानकारी संबंधित आवेदको को भी मिले ऐसी प्रक्रिया क्रियान्वित करें। उन्होंने आवेदको को लिखित रूप से अवगत कराने के निर्देश दिए है। समीक्षात्मक बैठक में सीएम हेल्पलाइन, सीएम मॉनिटरिंग, वरिष्ठ कार्यालयो से प्राप्त आवेदन तथा जनसुनवाई कार्यक्रम के लंबित आवेदनो पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा निराकरण के संबंध में क्या-क्या कार्यवाहियां संपादित कराई गई है कि जानकारियां विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपर कलेक्टर श्री डामोर ने निर्देश दिए है कि सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनो का निराकरण संतुष्टिपूर्वक समाधान कराया जाना सुनिश्चित करें इसके लिए उन्होंने एलवन स्तर पर ही आवेदक से जीवंत सम्पर्क साधने की सीख देते हुए कहा है कि आमने सामने बात करने पर आवेदक की समस्या का निराकरण में विलम्ब होने पर भी आवेदक अक्रोषित नहीं होते है। सम्पर्क बनाए रखने पर आवेदक को निराकरण की स्थितियां सांझा की ज सकती है। ऐसे आवेदन जिनका निराकरण जिला स्तर पर संभव नहीं है उन कारणो से भलीभांति अवगत कराएं और निराकरण की पहल हेतु विभाग प्रमुख को आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।

अपर कलेक्टर श्री डामोर ने हितग्राहीमूलक योजनाओं को क्रियान्वित कराने वाले विभागो के अधिकारियों से कहा है कि विभागीय योजना से संबंधित पात्रताधारक समय पर लाभांवित हो यह चिंता विभागीय जिलाधिकारी को होना चाहिए। ढीला रवैया अपनाने से अनेक प्रकार की दिक्कतो का सामना करना पडता है जब हमें मालूम है कि अमुक व्यक्ति योजना के हितलाभ हेतु पात्रता रखता है और उसे लाभ दिलाना है फिर विलम्बता क्यों। अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने धरती आबा योजना के तहत जिले में क्रियान्वित विशेष अभियान के संबंध में निर्देश दिए है कि चिन्हित 86 गांव में उक्त अभियान के तहत शत प्रतिशत हितलाभ दिलाया जाना है अतः अभियान के पूर्व संबंधित गांव में कुल कितने पात्रताधारक है किस-किस योजना से लाभ दिलाना है इत्यादि का डाटा शिविर आयोजन के पूर्व प्राप्त करें और उस गांव में पहुंचकर शेष वंचित रह गए हितग्राहियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर लाभ दिलाए साथ ही अभियान समाप्ति के उपरांत हितग्राहियों के गेप फीलिंग की पूर्ति पूरी हो सकें और शिविर के पहले और बाद में हितग्राहियों के लाभांवितों का डाटा स्पष्ट रूप से परलिक्षित हो। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु विशेष बल दिया। इस दौरान मुख्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कुल कितनी आईडी बनी है उनमें से कितनी क्रियाशील है कि सीएचओ एनएनएम , आंगनबाडी कार्यकर्ता, जीआरएस, ग्राम पंचायत के सचिव कि पृथक-पृथक जानकारियां आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के द्वारा नल से जल घर तक पहुंचाने के लिए जिन ग्रामो में नल जल योजना का कार्य संपादित कराया गया है उन ग्रामो में कार्य अवधि के दौरान जो सड़के क्षतिग्रस्त हुई थी उन सभी सडको का शत प्रतिशत मरम्मत कार्य कराया जा चुका है।

किसान भाई उर्वरक का अग्रिम भंडारण ना करें

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि रबी फसल के लिए उर्वरक का अग्रिम भंडारण न करें। उन्होंने बताया कि जिले में खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कलेक्टर श्री जैन सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित किसान संघ की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि उर्वरक का वितरण सोसाइटियों के माध्यम से कराया जाएगा। कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में किसान संघ के प्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में किसान संघ के पदाधिकारियो ने कलेक्टर श्री जैन को विद्युत कटौती, उर्वरक वितरण सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी को5 में विद्युत कनेक्शनयोजना का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी ने बताया कि जिले में क्षतिग्रस्त फूलों को बदलने का कार्य जारी है। करताना, सिराली व टिमरनी में नए पोल लगाए जा रहे हैं।

राइट क्लिक

बिहार: मुकाबला अब 'वोट चोरी' और 'वोट की रखवाली' के बीच है...

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा कथित 'वोट चोरी' को बिहार में मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने के मकसद से 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू कर दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ इन रैलियों में राहुल चुनाव आयोग और मोदी सरकार निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी और भाजपा हर चुनाव जीतते हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में जीतता है और 4 महीने बाद वहां भाजपा गठबंधन जीत जाता है। जब हमने थोड़ी जांच की, तो पता चला कि लोकसभा चुनाव के बाद, चुनाव आयोग ने 'जादुई' तरीके से महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाता बना दिए। लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ मतदाताओं का अंतर था। हालांकि महाराष्ट्र में मतदाताओं की गड़बड़ी के राहुल के दावे की सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार ने अपना ट्वीट वापस लेकर हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में दो सीटों पर वोटर डाटा की गणना में हमसे चूक हुई है। संजय कुमार ने ऐसा 'भूल स्वीकार' करने, ग्लानिवश अथवा किसी दबाव में ऐसा किया, यह अभी साफ नहीं है। लेकिन इस घटनाक्रम से सेफोलॉजिस्टों की साख भी सवालों के घेरे में आ गई है। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनसे हलफनामा देकर आरोप लगाने को कहा है ताकि आरोपों की सत्यता की जांच की जा सके। उन्होंने राहुल के 'वोट चोरी' जैसे शब्द प्रयोग को संविधान का अपमान बताया। बीजेपी भी चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। वैसे राहुल गांधी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो निष्पक्ष जांच से ही पता चलेगा और ऐसी कोई जांच होगी, इसकी संभावना भी कम है, लेकिन आजादी के बाद यह पहली बार है, जब चुनाव आयोग पर मैच 'रेफरी' की जगह' किसी टीम के सदस्य' के रूप में काम करने का गंभीर आरोप लगा है। संदेश जा रहा है कि आयोग जितना बता रहा है, उससे ज्यादा छुपा रहा है। अगर इसमें सच्चाई है तो यह हमारे लोकतंत्र को ही संदिग्ध बना देगा। लेकिन आरोप गलत सिद्ध हुए तो राहुल एंड टीम के लिए नैतिक मुसीबत खड़ी हो सकती है।

राहुल और विपक्ष जिस आक्रामक तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे लगता है कि उनका मुख्य लक्ष्य किसी तरह इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव तक खींचना है ताकि मतदाता के मन में यह शंका घर कर जाए कि राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह प्रायोजित है। विपक्ष को शंका है कि यह अभियान उसके वोटरों को लिस्ट से बाहर कर चुनाव जीतने की परोक्ष साजिश है। जबकि चुनाव आयोग का तर्क है कि बिहार में वोटर लिस्ट का 'शुद्धिकरण' एक सामान्य प्रक्रिया है। अप्रमाणित नामों को हटाया गया है। फिर भी कुछ नाम गलत हटे हैं तो उसे फिर जोड़ा जा सकता है। बावजूद इसके बिहार एसआईआर में 65 लाख मतदाता सूची से बाहर हुए हैं तो यह बड़ा आंकड़ा है। यानी राज्य में औसतन हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 27 वोटरों का कम होना। इतने अंतर से तो विस चुनाव में भारी हार-जीत हो जाती है। लेकिन विपक्ष की इस मुहिम का दूसरा खतरा यह भी वोटर उदासीन भी हो सकता है। उसे लग सकता है कि यदि सब कुछ गड़बड़ ही है तो वोट देने जाया ही क्यों जाए? लेकिन ऐसा हुआ तो इसका नुकसान विपक्ष को भी होगा और लोकतंत्र के नजरिए से यह नितांत अनुचित होगा।

अब सवाल यह है कि राहुल और विपक्ष वोट चोरी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्या अन्य मुद्दे धार खो चुके हैं? यहां ध्यान देने की बात यह है कि राजनीति में प्रमाण से ज्यादा धारणा (परसेप्शन) काम करती है। यानी आप वोट डलने तक यह माहौल बनाते रहे कि सुबह आपके हिसाब से ही होने वाली है, फिर भले रात हो जाए। विपक्ष को उम्मीद है कि चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाकर वोटर को इस बात के लिए विवश कर सकते हैं कि चूंकि चुनाव आयोग सरकार के अनुकूल काम कर रहा है, अतः उस सरकार को ही हटा दिया जाए। इससे विपक्ष का राजनीतिक मकसद पूरा हो जाएगा। अगर जीत गए तो आरोपों का सबूत कौन मांगता और कौन देता है। क्योंकि सत्ता सर्वोपरि है। जनता ने 'साजिशों' का जवाब दे दिया है और अगर हार गए तो कह देंगे कि हमने पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग और मोदी हमे हराने की साजिश रच रहे थे। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। ध्यान रहे कि राहुल जिस धारणा केन्द्रित लाइन पर बिहार चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सफल प्रयोग तत्कालीन विपक्ष और भाजपा काफी पहले कर चुके हैं। याद करें 1989 का लोस चुनाव, जिसमें बोफोर्स तोप खरीदी घोटाले में पूर्व पीएम राजीव गांधी को भ्रष्ट बताकर घेरा गया था। उन पर बोफोर्स तोप सौदे में मात्र 64 करोड़ की दलाली खाने का आरोप था। इस घोटाले की जांच में ही बीते 35 साल में 300 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और नतीजा आज तक निकला। यही फार्मूला पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान विभिन्न ठेकों में अरबों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर विपक्ष ने आजमाया। लेकिन ये मामले भी अब कोर्ट में टिक नहीं पा रहे हैं। और तो और मोदी सरकार उन्हीं मनमोहन सिंह का दिल्ली में स्मारक बनवा रही है। मनमोहनसिंह भ्रष्ट थे, यह कोई बेईमान भी शायद ही मान्य करे, लेकिन उनको सत्ता से हटाने का तात्कालिक मकसद पूरा हो गया। लेकिन 'नरो वा कुंजरो वा'रणनीति में केवल एक अर्जुन से ही काम नहीं चलता। उसी के साथ प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं और नेताओं की फौज और कुशल रणनीति भी चाहिए, जो संशय के बीज को वोट के ताबीज में बदल सके। वैसे भी चुनाव जीतना अब राजनीतिक शुचिता से ज्यादा मैनेजमैंट का विषय हो गया है। राहुल गांधी का सबसे कमजोर पक्ष यही है। वो मुद्दे तो पूरी ताकत से उठा रहे हैं। मोदी विरोधी उनकी इस 'हरक्युलियन अदा'पर फिदा हैं कि इस देश में कोई तो खम ठोककर मोदी और चुनाव आयोग को यह कहकर ललकार कर कह रहा है कि 'मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन वो अपनी पिछली गलतियों से सीखते भी हैं, ऐसा नहीं लगता। उनकी कार्यशैली 'चला जाता हूं, अपनी ही धुन में..' वाली ज्यादा है। 'चौकीदार चोर,' 'ईवीएम हैकिंग' और 'जाति जनगणना' वाले मुद्दों पर उन्हें अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिला। अलबत्ता लोकसभा चुनाव में 'संविधान बचाने' का मुद्दा कुछ राज्यों में जरूर हिट हुआ, लेकिन उसे रबर की तरह बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता। वैसे भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। दिल्ली और पटना में दूरी ही नहीं, तासीर का भी अंतर है। कोई मुद्दा तात्कालिक जोश के बजाए वोटर के मन में पैठकर उसे उद्वेलित कर दे तो चुनाव नतीजे बदल जाते हैं और उसमें चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर सकता।

लेकिन क्या बिहार ऐसा कुछ होगा? अभी यह कहना मुश्किल है। क्योंकि राहुल के संविधान बचाओ और वोट चोरी के आरोपों का जवाब भाजपा और सत्तारूढ़ एनडीए जनता को प्रसाद और रेवड़ी बांटकर दे रहा है। आश्चर्य नहीं कि चुनाव से पहले बिहार में भी 'लाडली बहना' जैसी कोई योजना घोषित हो जाए। राज्य में पहले ही से मतदाता को सीधा लाभ देने वाली लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा अविरत जारी है। ऐसे में वोटर हाथ आ रहे लाभ को तरजीह देगा या 'चुनाव आयोग और नीतीश सरकार को सबक सिखाने' के लिए सत्ता विपक्षी महागठबंधन को जयमाला पहनाएगा, यह देखने वाली बात है। रहा सवाल चुनाव आयोग का तो उसे अपनी विश्वसनीयता खुद साबित करनी है। उसके हर काम में पारदर्शिता और प्रामाणिकता हो, यह लोकतंत्र का बुनियादी तकाजा है। वह चाहता तो राहुल गांधी से हलफनामा मांगे बगैर भी चुनाव और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की अपने स्तर पर स्वतंत्र जांच करा कर राहुल गांधी को करारा जवाब दे सकता था। लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है। हालांकि समूची चुनाव प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है। उसमे कुछ त्रुटियां होना असंभव नहीं है बल्कि होती ही हैं। लेकिन उनका निदान हो सकता है। देश में 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में चुनाव आयोग ने 27 लाख गलत नाम मतदाता सूची से हटाए थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। लेकिन तब किसी ने एतराज नहीं किया। अब आयोग के हर काम और मंशा पर संशय क्यों? कुल मिलाकर बिहार का विधानसभा चुनाव जनता के इस फैसले का चुनाव भी बनता जा रहा है कि उसे भरोसा किस बात पर है, वोट चोरी पर या वोटों की रखवाली पर आगे आगे देखिए, होता है क्या?

एमसीयू का सत्रारंभ कार्यक्रम 'अभ्युदय' आरंभ

सीएम ने किया एमसीयू में माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का अनावरण

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने पिछले पैंतीस वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। यहां से शिक्षा प्राप्त पत्रकारों ने मीडिया की दुनिया में मानक स्थापित किए हैं। वे यहां माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के अकादमिक सत्र 2025-2026 का सत्रारंभ समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से बोल रहे थे। इस मौके पर प्रख्यात कवि डॉ. कुमार विश्वास, विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी, राज्य शासन में मंत्री कृष्णा गौर, मेयर मालती राय, विधायक भगवान दास सबनानी, रामेश्वर शर्मा, उमाकांत शर्मा, जनसम्पर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने दादा माखनलाल चतुर्वेदी की 12 फीट उंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान अतिथियों ने परिसर में पौधरोपण भी किया। माखनलाल चतुर्वेदीजी की पत्रकारिता से जुड़े रतौना प्रसंग तथा ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता पर चर्चा करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि एमसीयू ने आज भी उस परंपरा को जीवित रखा है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जाने माने कवि और रामकथा विशेषज्ञ डॉ. कुमार विश्वास ने कहा कि समाज का आज भी छपे हुए और बोले हुए शब्दों पर भरोसा कायम है। इस विश्वास को कायम रखना आने वाली पत्रकार

पीढ़ी की जिम्मेदारी आज मीडिया में थोपे गए विषय नेपथ्य में जा रहे हैं और देश तथा समाज से जुड़े जो अहम विषय पहले नजरअंदाज कर दिये जाते थे आज वे पत्रकारिता में प्रमुखता से नजर आने लगे हैं। डॉ. विश्वास ने कहा कि किसी विचार को केंद्र में रखते हुए भी तटस्थ होकर लिखना ही पत्रकारिता है। सत्रारंभ के पहले दिन साफ्ट स्किल्स पर संवाद करते हुए वरिष्ठ संपादक और लेखक एन. रघुरामन ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए लोगों से व्यवहार करने का कौशल,पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना, क्रोध को काबू में रखने के कौशल जैसे गुण बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में सॉफ्ट स्किल्स एक आवश्यक गुण है। इसके बाद एनिमेशन की दुनिया से जुड़े वरिष्ठ फिल्मकार तथा विशेषज्ञ आशीष कुलकर्णी ने एआई के दौर में बदलती तकनीकों पर संवाद किया।

उन्होंने कहा कि आज के दौर में हर कार्यक्षेत्र में तकनीक का समावेश हो चुका है। आने वाले दौर में मीडिया में वीडियो, वर्नाकुलर (क्षेत्रीय कंटेंट) और वाइस का बहुत योगदान बढ़ने वाला है। आज के अलग-अलग सत्रों में विश्वविद्यालय की पूर्व छात्राओं निधि परमार, जूही कुलश्रेष्ठ तथा स्वाति कौशिक ने भी विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन और अनुभवों से जुड़े विचार साझा किए। उद्घाटन सत्र में विनय उपाध्याय तथा बाद के सत्रों में प्रो. सीपी अग्रवाल, डॉ. अविनाश वाजपेयी तथा डॉ. अनीता सोनी ने संचालन किया। कार्यक्रम के अंतिम सत्र के बाद आभार विवि की कुलसचिव प्रो. डॉ. पी. शशिकला ने किया। कुलगुरू विजय मनोहर तिवारी ने नवागंतुक विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि वे निरंतर अध्ययन करते रहें तथा अपने अभिभावकों की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। कुलगुरू ने यह भी कहा कि आगामी समय में विश्वविद्यालय एआई, डीप फेक और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए विषयों पर नए पाठ्यक्रम आरंभ करेगा।

बढ़ती हुए टैरिफ में भूरे बालों वाला फूफा चिंतित है : कुमार विश्वास

विश्वास ने कहा कि बढ़ती हुई टैरिफ में वो जो एक भूरे बालों वाला फूफा है। उसने हद कर दी है। वो दिन में तीन ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नस कांट लूंगा। अरे भाई तुझसे कोई बात नहीं कर रहा है तू अपना काम करे। एक स्वाधीन देश है और दूसरे प्रकार का नेतृत्व है। यह (पीएम) ऐसी आर्म ट्विस्टिंग करने वालों के साथ क्या करता है ना पता हो तो कांग्रेस में दोस्त हैं, उनसे पूछ ले। वो बता देंगे।सभी छात्रों को इसपर अध्ययन करना चाहिए कि बढ़ती हुई टैरिफ की धमकी के बीच देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले कर जा सकते हैं। इस दौर में एक छोटा व्यापारी कैसे बड़ा बन सकता है। सुबह उठता हुं, टूथ पेस्ट हो या ब्रश सब बाहरी कंपनी के होते हैं। क्या भारत इतनी छोटी चीजें नहीं बना सकता है। इसपर ध्यान देने की जरूरत है।

मुझे विद्यार्थी दे दीजिए, जहाज पकड़ के आ जाऊंगा

कवि कुमार विश्वास ने कहा, शुद्ध रूप से कवि सम्मेलन की व्यावसायिकता को ऊपर ले जाने में मैंने काफी श्रम किया। जिसमें काफी सफलता भी मिली। उस व्यावसायिकता के खांचे में यह कार्यक्रम फिट नहीं बैठता है। ऐसे में कुलगुरु ने मुझसे पूछा कि हम आपको क्या दे सकते हैं तो मैंने कहा आप सिर्फ मुझे विद्यार्थी दे दीजिए। मैं जहाज पकड़ कर खुद आ जाऊंगा। आगे की सीट में जो सज्जन बैठें हैं, सभी परिचित हैं। यह संवाद के स्तर से ऊपर उठ गए हैं। मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि इन्हें कुछ बोल कर सुधार दूंगा या कुछ सिखा दूंगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की।

मंत्री तोमर ने टॉयलेट साफ किया, स्वास्थ्य अधिकारी को माला पहनाई

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जिला अस्पताल के टॉयलेट में गंदगी और बदबू से नाराज हो गए। उन्होंने अपने हाथों से टॉयलेट साफ किया। इसके बाद जब वे लुहारपुरा की पुलिया से गुजर रहे थे। यहां कचरे के ढेर को देख गाड़ी रुकवाई। फावड़ा उठाकर सफाई करने में जुट गए।

अभी माला पहनाई, कल सम्मान के साथ विदा कर दूंगा

स्थानीय लोगों ने शहर में सफाई को लेकर मंत्री तोमर से शिकायत की। इसके बाद तोमर ने मौके पर नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी योगेश शर्मा को माला पहनाई। फिर कहा-आज तुम्हें माला पहनाई है, कल सम्मान के साथ विदा कर दूंगा। मेरी बात को गंभीरता से लेना।मंत्री ने सफाई मशीन बुलवाने के निर्देश दिए और मौके से निकल गए।

शिकायतों के बाद मंत्री ने किया निरीक्षण

हाल ही में जिला अस्पताल के गेट पर आदिवासी महिला की डिलीवरी और इलाज में लापरवाही की शिकायतें सामने आई थीं। अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया के आने पर भी रोक लगा दी थी।

इन्हीं शिकायतों के बाद प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बुधवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे।

खोजी पत्रकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो भगवान हनुमान से बेहतर कोई नहीं : सीएम यादव

भोपाल (नप्र)। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में बुधवार को नए शैक्षणिक सत्र अभ्युदय-2025 की शुरुआत हुई। खोजी पत्रकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान हनुमान- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यदि खोजी पत्रकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो भगवान हनुमान से बेहतर कोई नहीं। लंका जाने के दौरान उन्होंने परिस्थितियों की परवाह किए बिना हर जानकारी गहराई से जुटाई। अपनी जान हथेली पर रखकर जो आकलन और खोज उन्होंने की, वह पत्रकारिता की असली मिसाल है। हालात जैसे भी हों, उसके अनुसार स्वयं को ढाल लेना कभी साधारण रूप तो कभी विकराल रूप यह सब हनुमानजी से सीखने योग्य गुण हैं।डॉ. यादव ने कहा कि हमें गर्व है कि माखनलाल चतुर्वेदी हमारे मध्यप्रदेश के थे। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों में 'कुलपति' की जगह 'कुलगुरु' शब्द अपनाने के पीछे का किस्सा भी साझा किया। उन्होंने कहा जब मैं शिक्षा मंत्री के रूप में इंदौर गया था, तब एक विश्वविद्यालय की कुलपति (वाइस चांसलर) के पति से भेंट हुई। उन्होंने अपना परिचय इस तरह दिया कि मैं आपके कुलपति का पति हूं। यह सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। तभी मैंने तय कर लिया कि इस गलत शब्द को बदलना ही होगा। दरअसल अंग्रेजी के वाइस चांसलर का अनुवाद हिंदी में 'कुलपति' कर दिया गया था, जो त्रुटिपूर्ण था। इसके बाद हमने महाराष्ट्र से जानकारी ली, जहां इसे 'कुलगुरु' कहा जाता है।

कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते के गले में बांधा ज्ञापन

छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किसान आंदोलन ; पटवारी ने दिया नारा- खाद चोरों, कुर्सी छोड़ो

छिंदवाड़ा (नप्र)। कांग्रेस ने खाद की कमी और किसानों की अलग-अलग समस्याओं को लेकर छिंदवाड़ा में बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प और धक्का-मुक्की देखने को मिली। कांग्रेस नेता कलेक्टर को किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन जब कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते को ज्ञापन सौंपा गया। कुत्ते के गले में ज्ञापन बांध दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने ज्ञापन बंधे कुत्ते को ऊपर उठाया। इस दौरान पूर्व सांसद नकुलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली- इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर रैली निकाली। जिसमें प्रदेशभर से किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। रैली सभा स्थल जेल बगीचे तक पहुंची। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व सांसद नकुलनाथ समेत कई कांग्रेस नेताओं ने सभा को संबोधित किया। जीतू पटवारी ने कहा- प्रदेश में खाद की कमी बनी हुई है और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर किसान लाइन में क्यों लगे हैं। पुलिस उन पर डंडे क्यों चला रही है। जीतू पटवारी ने नारा दिया- 'खाद चोरों, कुर्सी छोड़ो'

नकुलनाथ ने कहा- मैं शासन-प्रशासन और पुलिस को चेतावनी देना चाहता हूं। आपने आदिवासी दिवस पर आदिवासियों पर एफआईआर की...जब किसान अपना हक, अपना अधिकार मांगने यूरिया के लिए कतार में खड़ा हुआ, आपने किसानों पर एफआईआर की। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों पर एफआईआर करोगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? हम सब गिरफ्तार होने को तैयार हैं।